twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

DD दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 249, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

पुलिसकर्मियों की सुविधा को योगी सरकार ने खोला खजाना

26वीं वाहिनी पीएसी परिसर में 11 मंजिला बैरक टॉवर का को मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण

गोरखपुर/एजेंसी

पुलिस मकहमे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने तथा इसके जरिये पुलिसकर्मियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने खजाना खोल रखा है। अकेले गोरखपुर में पुलिस, पीएसी, पीएसी महिला बटालियन और विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) के लिए हो रहे आठ सौ करोड़ रुपये से अधिक के कार्य इसका प्रमाण हैं। यहां जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हैं, वे सभी पुलिकर्मियों को सुविधानजक वातावरण उपलब्ध कराने से संबंधित हैं। इनमें से एक प्रोजेक्ट 26वीं वाहिनी पीएसी में 11 मंजिला बैरक टॉवर भी है, जिसका लोकार्पण को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके अलावा पीएसी महिला बटालियन, पीटीएस, एसएसएफ के भवन और पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कार्य अगले साल तक पूरा हो जाएगा। 26वीं वाहिनी पीएसी (प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी) गोरखपुर परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुमंजिला बैरक बनाया गया है। 11 मंजिला बैरक टॉवर बनाने के लिए 11 करोड़ 67 लाख रुपये की लागत स्वीकृत की गई थी। टॉवर के भूमि तल पर डायनिंग हाल, लॉबी किचन, बरामदा, टॉयलेट, दो लिफ्ट, दो स्टेयरकेस

का निर्माण कराया गया है। टॉवर के प्रथम तल पर डायनिंग हाल, ओपेन टैरेस, लॉबी, रिक्रिएशन हाल, टॉयलेट, लिफ्ट, स्टेयरकेस निर्मित है। जबकि द्वितीय तल से 11वें तल तक प्रत्येक फ्लोर पर चार कमरे बनवाए गए हैं। हर कमरा पांच जवानों की क्षमता का है। इसके अलावा चार टॉयलेट, लिफ्ट और स्टेयरकेस का निर्माण हुआ है।

कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग (भवन खंड) द्वारा बनाए गए इस बैरक टॉवर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आरसीसी टैंक, सेप्टिक टैंक, विद्युत आपूर्ति हेतु डीजी सेट, फायर सेफ्टी आदि की भी व्यवस्था की गई है।

गोरखपुर में पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जारी कार्य

-पीएसी की महिला बटालियन के लिए 225 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय भवनों का निर्माण जून 2026 तक पूरा हो जाएगा।

-पीएसी की महिला बटालियन के लिए 119 करोड़ रुपये की लागत से अनावासीय भवनों का निर्माण अगस्त 2026 तक पूरा हो जाएगा।

-पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता दोगुना करने के लिए 41 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय भवनों का निर्माण मार्च 2026 तक पूर्ण हो जाएगा।

-पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता दोगुना करने के लिए 125 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय भवनों का निर्माण मार्च 2026 तक पूर्ण हो जाएगा।

-विशेष सुरक्षा बल, द्वितीय वाहिनी के लिए 81 करोड़ रुपये की लागत से अनावासीय भवनों का निर्माण जून 2026 तक पूरा हो जाएगा।

-विशेष सुरक्षा बल, द्वितीय वाहिनी के लिए 186 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय भवनों का निर्माण जून 2026 तक पूरा हो जाएगा। पुलिस लाइन में 28 करोड़ रुपये की लागत से बहु मंजिला ट्रांजिट हॉस्टल के दो ब्लॉक का निर्माण मार्च 2026 तक पूर्ण हो जाएगा।

विकास में लगा पैसा जनता का, सुनिश्चित हो सही इस्तेमाल: मुख्यमंत्री योगी

गोरखपुर/एजेंसी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों में नागरिकों के सकारात्मक रुख और सहयोग की सराहना करने के साथ कहा है कि विकास में लगने वाला पैसा जनता जनार्दन के टैक्स का है। इस पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होना चाहिए। विकास कार्यों में क्वालिटी (गुणवत्ता) से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। विकास के लिए जनता के पैसे का सही उपयोग हो, यह हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। सीएम योगी गोरखपुर नगर निगम परिसर में स्वच्छ सर्वेक्षण में गोरखपुर को राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि दिलाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सफाई मित्रों के सम्मान और 253 करोड़ रुपये की 177 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी नागरिकों को सावन माह की शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सफाई मित्र सुरक्षित शहर श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही गोरखपुर को 3 से 10 लाख की आबादी की श्रेणी

में चौथी नेशनल रैंक मिली है। जबकि गत वर्ष गोरखपुर 24वें और उसके पहले 74वें स्थान पर था। तीन साल में गोरखपुर की स्वच्छता रैंकिंग 74 से चौथे स्थान पर आने को बड़ी उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री कहा है कि अब अगली प्रतिस्पर्धा टॉप-थ्री में आने की होनी चाहिए और इसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा।

स्वच्छता में नम्बर एक ओर भी आ सकता है गोरखपुर

मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि गत वर्ष उन्होंने गोरखपुर को स्वच्छता के लिए टॉप-टेन शहरों में आने का टारगेट दिया था। यह टारगेट पूरा कर लिया गया है। गोरखपुर अपनी श्रेणी में नम्बर एक पर भी आ सकता है, इसलिए हम सबको अगले साल के लिए टॉप-थ्री का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना होगा और इसमें सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।

सीएम योगी ने लोगों को याद दिलाया कि पहले गोरखपुर को लेकर क्या चर्चा होती थी। कहा कि पहले गोरखपुर की चर्चा, मच्छर, माफिया, गंदगी, अव्यवस्था और अराजकता को लेकर होती थी। बुनियादी सुविधाओं के अभाव से त्रस्त पूरा शहर जाम में फंसा रहता था। एक बारिश में शहर जलमग्न हो जाता था। आज इन सबसे निजात मिल चुकी है। अब एक नए भारत के लिए नए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर भी एक नया गोरखपुर बनकर दिखा है। उन्होंने कहा कि जब एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी होती है।

भारत और ब्रिटेन को लंदन में एफटीए पर करेंगे हस्ताक्षर

नई दिल्ली/एजेंसी

भारत और ब्रिटेन को लंदन में बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौते से श्रम-प्रधान उत्पादों जैसे चमड़ा, जूते और कपड़ों का रियायती दरों पर निर्यात संभव होगा, जबकि ब्रिटेन से व्हिस्की और कारों का आयात सस्ता हो जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की मौजूगी में भारत और ब्रिटेन एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्?य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। इस समझौते से चमड़ा, जूते और कपड़ों जैसे श्रम-प्रधान उत्पादों का रियायती दरों पर निर्यात करना संभव होगा, जबकि ब्रिटेन से व्हिस्की और कारों का आयात सस्ता हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव के चार दिवसीय दौरे पर बुधवार को रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री 23-24 जुलाई को ब्रिटेन में रहेंगे, जहां उनके ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से द्विपक्षीय बातचीत और कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस समझौते को आधिकारिक तौर पर एक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कहा जाता है। इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को 2030 तक दोगुना कर-के 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने में भी मदद करेगा।

एअर इंडिया विमान में टेकऑफ के बाद आई तकनीकी खराबी

नई दिल्ली/एजेंसी

टाटा की अगुवाई वाली विमानन कंपनी एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों में लगातार तकनीकी खराबियों के मामले सामने आ रहे हैं। केरल के कालीकट (कोझिकोड) से बुधवार को कतर की राजधानी दोहा जा रहे एयर इंडिया के विमान को उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद तकनीकी खराबी के कारण वापस कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पायलटों और चालक दल सहित 188 लोगों को लेकर उड़ान संख्या क 375 ने सुबह लगभग 9.07 बजे कालीकट से उड़ान भरी थी।

बब्बर खालसा का आतंकी इंदौर से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी

नई दिल्ली/एजेंसी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़े एक आतंकी आकाश दीप उर्फ बज्ज (22) को गिरफ्तार किया है। आकाश दीप पंजाब के बटाला में किला लाल सिंह पुलिस चौकी पर 7 अप्रैल को हुए ग्रेनेड हमले में शामिल था। इसके अलावा वह दिल्ली में अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में भी वांछित था। पुलिस ने उसे इंदौर से पकड़ा, जहां वह क्रेन ऑपरेटर बनकर छुपा हुआ था। दिल्ली पुलिस के डीसीपी अमित कौशिक ने बताया कि आकाश दीप से पूछताछ की जा रही है और वह लगातार चौंकाने

वाले खुलासे कर रहा है। शुरूआती पूछताछ में उसने बताया कि वह बीकेआई के एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में था जो सोशल मीडिया ऐप के जरिए उसे निर्देश देता था। आकाश दीप उसी के कहने पर भारत में आतंकी गतिविधियां अंजाम दे रहा था। बटाला में हुए ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी बीकेआई ने ली थी। यह हमला पीलीभीत एनकाउंटर के जवाब में किया गया था, जिसमें तीन संदिग्ध मारे गए थे। अब दिल्ली पुलिस और एनआईए यह जांच कर रही हैं कि बीकेआई का यह नेटवर्क भारत में और किन-किन राज्यों में फैला हुआ है और इसके विदेशी हैंडलर कौन-कौन हैं। बताया जा रहा है कि आकाश दीप सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपने हैंडलर से संपर्क में रहता था और भारत में हथियारों की तस्करी से लेकर आतंकी हमलों तक की योजनाएं बना रहा था। पुलिस अब उसके संपर्क में रहे दूसरे लोगों की भी तलाश कर रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कर्नल सोफिया कुरैशी की टिप्पणी पर विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग

नई दिल्ली/एजेंसी

कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान के मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता डॉ. जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में मंत्री विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि मंत्री विजय शाह ने संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत ली गई मंत्री पद की शपथ का उल्लंघन किया है।उनका सार्वजनिक मंच पर दिया गया बयान सांप्रदायिक भेदभाव फैलाने वाला और देश में धार्मिक

सौहार्द्र को नुकसान पहुंचाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को विजय शाह के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच में शामिल होने की शर्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी के गठन का आदेश दिया था। विजय शाह की ओर से मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। दरअसल, इंदौर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना विवादित बयान दिया था। इस बयान के बाद काफी हंगामा खड़ा हुआ था।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद विजय शाह पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

तेजस्वी अपने माता-पिता का कार्यकाल याद करें : मुख्यमंत्री

पटना/एजेंसी

बिहार विधानमंडल (विधानसभा-विधानपरिषद) में मानसून सत्र का तीसरा दिन विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध और हंगामे की भेट चढ़ गया। दोनों सदनों में बुधवार को मतदाता पुनरीक्षण पर जमकर हंगामा हुआ। दूसरी पाली में विपक्ष के वॉकआउट के बाद विधानसभा से 6 विधेयक हुए पारित हुए। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बिहार विधानसभा की दूसरी पाली में आज जननायक कपूर्री ठाकुर कौशल विधेयक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, कारखाना संशोधन विधेयक, बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक 2025, बिहार प्लेटफार्म आधारित गिग कामगार विधेयक, बिहार दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक समेत कुल 6 बिल पारित हुए। विपक्ष के वॉकआउट के बीच विधानसभा की दूसरी पाली 58 मिनट चली। इसके बाद सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विधान परिषद में भी दूसरी पाली में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। द्वितीय पाली शुरू होते ही विपक्षी सदस्य मतदाता पुनरीक्षण का विरोध करते हुए वेल में आ गए। इसके पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि सरकार एसआईआर के माध्यम से वोटबंदी करा रही है। सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा के संजय मयूख, अनिल कुमार और प्रमोद कुमार ने विपक्ष के बयान का विरोध किया। वेल में राजद, कांग्रेस, भाकपा और भाकपा (माले) के सदस्यों की नारेबाजी के बीच बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास संशोधन विधेयक 2025

2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली/एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के मामले में 12 आरोपितों को बरी किए जाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आज महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस याचिका को चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन कर जल्द सुनवाई की मांग की गई तो चीफ

जस्टिस ने कहा कि इसमें जल्दबाजी क्या है। इस मामले में पहले ही आठ लोगों की रिहाई हो चुकी है।

दरअसल, सितंबर 2015 में निचली अदालत ने पांच को मौत की सजा और सात को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस सजा को आरोपितों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को फैसला सुनाते हुए 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में 12 आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है।

फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई

नई दिल्ली/एजेंसी

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए और यही उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने केन्द्र सरकार पर संविधान से विपरीत कार्य करने का आरोप लगाया और कहा कि जो किया गया है, वह अवैध है और उसे वापस लिया जाना चाहिए।

फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आज डिप्टी स्पीकर हॉल, कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

इसी में फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि हम उनके आगे झुकें, लेकिन हम झुकने या भीख मांगने नहीं आए हैं। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो उन्होंने किया, वह अवैध है। उन्हें राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए।

बरसात में होने वाली बीमारियों के खिलाफ चल रहा है देशव्यापी सफाई अभियान

नई दिल्ली/एजेंसी

बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई महीने में सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान शुरू किया है। शहरी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की देखरेख में चलने वाले इस अभियान में देश के अलग-अलग शहरों में साफ-सफाई, बीमारियों से बचाव और लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत पटना नगर निगम ने इस अभियान में एक पहल करते हुए मैनहोल एम्बुलेंस शुरूआत की है। ये एम्बुलेंस निगम के पुराने वाहनों को ठीक करके तैयार की गई है।

इनमें मैनहोल ढंकने और मरम्मत करने के लिए जरूरी सामान और एक टीम मौजूद रहती है। बारिश के समय अगर कोई मैनहोल खुला हो या टूट गया हो, तो यह एम्बुलेंस तुरंत मौके पर जाकर मरम्मत करती है। फिलहाल पटना में ऐसी छह एम्बुलेंस काम कर रही हैं, जो शिकायत मिलते ही तुरंत पहुंच जाती हैं। दिल्ली नगर निगम ने भी इस अभियान के तहत कई काम किए हैं। दक्षिणी दिल्ली में 400 एनसीसी लड़कियों ने मिलकर 'पिंकथॉन' नाम की एक वॉकथॉन निकाली। इसमें बच्चों को स्कूलों में हाथ धोने के सही तरीके सिखाए गए। कई गलियों और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई की गई। वहीं संसद भवन और दूसरी जगहों पर मच्छर भगाने के लिए फॉगिंग भी की गई और नालियों की सफाई कराई गई ताकि पानी न भरे। नवी मुंबई में भी स्वच्छता रैली निकाली गई जिसमें छात्र, माता-पिता और स्थानीय लोग शामिल हुए। यहां मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए 26 स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाए गए, जिनमें हजारों लोगों ने भाग लिया। सफाईकर्मियों ने शहर के कई हिस्सों में सफाई अभियान चलाया। तेलंगाना में घर-घर जाकर लोगों को बताया गया कि गीला और सूखा कचरा अलग कैसे करें। यहां की नालियों की सफाई की गई, सड़कों के किनारे झाड़ियां हटाई गईं और लगभग दो लाख

गाजियाबाद में अवैध दूतावास का एसटीएफ ने किया भंडाफोड़, संचालक गिरफ्तार

एजेंसी

गाजियाबाद। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद साइबर क्राइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और तमाम अवैध धंधों का हब बनता जा रहा है। पुलिए ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा इकाई ने मंगलवार की रात में दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक पॉश कालोनी कविनगर में चल रहे एक अवैध दूतावास का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने इस अवैध दूतावास के संचालक को गिरफ्तार कर वहां से 44 लाख 70 हजार रुपये सहित कई डिप्लोमेटिक गाड़ियों की नंबर प्लेट और गाड़िया बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपित खुद को कई देशों का एम्बेस्डर बताता था। एसटीएफ आरोपित से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम जिले के कवि नगर थाने में सूचना देने के बाद मंगलवार रात करीब 10 बजे कविनगर में स्थित एक कोठी नंबर केबी 45 पर बने कथित दूतावास पर पहुंची। एसटीएफ के साथ कवि नगर थाने का एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही भी मौके पर पहुंचे। यहां एसटीएफ ने हर्षवर्धन जैन नामक युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। इसके बाद एसटीएफ ने अवैध दूतावास संचालक हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार

कर लिया है। एसटीएफ ने उसके मकान से 44 लाख 70 हजार रुपये नकद, कई देशों की विदेशी मुद्रा, 20 डिप्लोमेटिक गाड़ियों की नंबर प्लेट, चार डिप्लोमेटिक नम्बर प्लेट लगी गाड़ियां, माइक्रोनेशन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मोहर लगे कूटरचित दस्तावेज, कूटरचित दो पैनकार्ड, विभिन्न देशों और कई कंपनियों की 34 मोहरें, 2 कूटरचित प्रेस कार्ड, कई देशों की विदेशी मुद्रा सहित अन्य सामान बरामद किया। छापे के दौरान उसके मकान में उसके ससुर आनंद जैन, भाटिया मोड़ निवासी ईश्वर सिंह और घरेलू सहायक हेमंत कुमार राजवंशी भी मिले। ईश्वर और हेमंत को एसटीएफ ने गवाह बनाया। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि गिरफ्तार हर्षवर्धन जैन कवि नगर में एक किराए की कोठी में अवैध रूप से वेस्ट आर्कटिक का दूतावास चला रहा था। वह अपने आप को कई देशों एम्बेसडर बताता था। वह लोगों को प्रभाव में लेने के लिए प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति और कई अन्य गणमान्यों के साथ एडिट कर अपनी फोटो का भी प्रयोग करता था। एडीजी ने बताया कि इस संबंध में थाना कविनगर गाजियाबाद में अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार हर्षवर्धन पुत्र जेडी जैन कविनगर इलाके में एक किराए के मकान में अवैध रूप से वेस्ट आर्कटिक दूतावास चला रहा था।

भारतीय नौसेना के चार जहाजों की सिंगापुर यात्रा पूरी, समुद्री सहयोग पर हुई चर्चा

एजेंसी

नई दिल्ली। दक्षिण पूर्व एशिया में तैनाती के दौरान पूर्वी बेड़े ?के जहाजों दिल्ली, शक्ति, सतपुड़ा और किल्टन ने सिंगापुर बंदरगाह पर अपनी यात्रा पूरी कर ली है। पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल सुशील मेनन के नेतृत्व ने इन जहाजों की 16 से 19 जुलाई तक परिचालन तैनाती की गई थी। यात्रा के दौरान सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के फ्लीट कमांडर से मुलाकात हिंद-प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय नौसैनिक संबंधों और समुद्री सहयोग को बढ़ाने के अवसरों और संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस यात्रा के दौरान रियर एडमिरल सुशील मेनन ने समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास पर भारतीय नौसेना के दृष्टिकोण पर अकादमिक समुदाय के साथ अनौपचारिक चर्चा की। पूर्वी बेड़े के जहाजों के कमांडिंग अधिकारियों ने क्रांजी युद्ध स्मारक पर भव्य पुष्पांजलि समारोह में भाग लिया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नौसेनाओं के बीच व्यावसायिक बातचीत में क्रॉस-डेक दौरे, विषय वस्तु विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और मैत्रीपूर्ण खेल गतिविधियां शामिल थीं, जिनका उद्देश्य अंतर-संचालन और आपसी समझ को मजबूत करना था। इसी दौरान आईएनएस शक्ति पर एक डेक रिसेप्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सिंगापुर नौसेना के कर्मियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, राजनयिक समुदाय के सदस्यों और भारतीय प्रवासियों ने समुद्री साझेदारी के बंधनों का जश्न मनाया। सिंगापुर बंदरगाह पर भारतीय नौसेना की यात्रा ने क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और समुद्री सहयोग के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता और योगदान को उजागर किया, जो क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार, विशेष बेंच का होगा गठन

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग कपिल सिब्बल ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिया है कि इस मामले के लिए जल्द ही एक विशेष बेंच का गठन किया जाएगा। हालांकि चीफ जस्टिस बी. आर. गवई इसका हिस्सा नहीं होंगे। वकील कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी और सिद्धार्थ लूथरा जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से पेश हुए। कपिल सिब्बल ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला उठाते हुए कहा, इस मामले में कई संवैधानिक पहलू जुड़े हैं। हम आग्रह करते है कि इस अर्जी पर जल्द सुनवाई के लिए बेंच का गठन करें। सिब्बल के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने इस दिशा में कदम उठाने का फैसला किया। विशेष बेंच के गठन के बाद इस मामले की सुनवाई की तारीख जल्द तय की जाएगी। सीजेआई बी. आर. गवई इस मामले के लिए ऐसी बेंच का गठन करेंगे, जिसमें वह खुद न हो। विभिन्न विपक्षी दलों के 63 राज्यसभा सांसदों ने सोमवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सभापति को प्रस्ताव का नोटिस सौंपा। कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ यह नोटिस सौंपा गया था। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को इसकी जानकारी दी थी। न्यायमूर्ति शेखर यादव को हटाने के लिए इसी तरह का प्रस्ताव 13 दिसंबर, 2024 को राज्यसभा के सभापति को सौंपा गया था। इससे पहले संसद के मानसून सत्र का आगाज होते ही 145 लोकसभा सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए लोकसभा स्पीकर को ज्ञापन सौंपा। सांसदों ने संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत यह कदम उठाया है।

पीएम मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना, ठोस परिणामों की उम्मीद

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ब्रिटेन (यूके) और मालदीव की द्विपक्षीय यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करेगी और इसके ठोस परिणाम सामने आएंगे। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा 23-24 जुलाई के बीच होगी, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के निमंत्रण पर हो रही है। यह पीएम मोदी की चौथी ब्रिटेन यात्रा है। यात्रा से पहले जारी अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जिसने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारा सहयोग व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, शिक्षा, अनुसंधान, सतत विकास, स्वास्थ्य और लोगों से लोगों के संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। उन्होंने बताया कि वह प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी, ताकि समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि वह ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 25-26 जुलाई को मालदीव की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर हो रही है। यह प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव की तीसरी यात्रा है और राष्ट्रपति मुइज्जू के कार्यकाल में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली आधिकारिक यात्रा होगी। इस यात्रा का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यही नहीं, इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है।

आईडीईएस, एमईएस और सीडब्ल्यूईएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने की राष्ट्रपति से मुलाकात

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से बुधवार को भारतीय रक्षा संपदा सेवा (आईडीईएस), मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज (एमईएस) और केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा (सीडब्ल्यूईएस) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने तीनों सेवाओं के अधिकारियों को संबोधित किया और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। राष्ट्रपति ने आईडीईएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के तकनीकी युग में डिजिटल समाधानों का समावेश आवश्यक हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन आधारित भूमि सर्वेक्षण, सैटेलाइट इमेजरी और ब्लॉकचेन तकनीक अब भविष्य की नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकताएं बन गयी हैं। राष्ट्रपति ने उनसे आग्रह किया कि वे हरित बुनियादी ढांचा विकास को अपनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें, जल संरक्षण सुनिश्चित करें और अपव्यय को कम करें। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य निर्माण के क्षेत्र में

युवा एमईएस अधिकारी केवल निर्माणकर्ता नहीं, बल्कि उत्तरदायी निर्माता भी हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र के निर्माण कार्यों में सतत विकास को सुनिश्चित करना समय की मांग है। राष्ट्रपति ने 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के तहत स्वदेशी तकनीकों और सामग्री को प्रोत्साहित करने के लिए एमईएस की सराहना की।

केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन जल सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में। उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल की उपलब्धता और जल संरक्षण न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, बल्कि कृषि उत्पादकता भी बढ़ाएंगे और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सीडब्ल्यूईएस अधिकारियों से कहा कि वे जल संकटों से निपटने के लिए सुदृढ़ जल संरचनाओं और अभियांत्रिकी समाधानों के माध्यम से राष्ट्र को अधिक सशक्त और संवेदनशील बनाएं। राष्ट्रपति ने तीनों सेवाओं के अधिकारियों को राष्ट्र सेवा के उनके संकल्प के लिए शुभकामनाएं दीं और उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से निभाने की प्रेरणा दी।

मोदी सरकार में बिहार को रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास की सौगात मिली: अश्विनी वैष्णव

एजेंसी

नई दिल्ली । रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास की सौगात मिली है। जहां 11 साल पहले बिहार को रेलवे बजट में मात्र 1,132 करोड़ रूपये की राशि मिलती थी, वहीं अब यह राशि बढ़कर 10,000 करोड़ रूपये हो गई है। यह बिहार के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रेल मंत्री ने कहा कि कई वर्षों से लंबित प्रोजेक्ट्स को एनडीए सरकार ने पूरा किया है। मुंगेर और पटना में नए ब्रिज बनाए गए हैं और कोसी ब्रिज, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मंजूरी दी थी, उसे अब मोदी सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार के साथ न्याय केवल एनडीए ही कर सकती है। सीतामढ़ी-शिवहर रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने बताया कि बागमती नदी पर जो पुल बनना है, उसका टेंडर हो चुका है। देकुली धाम को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को

लेकर 262 करोड़ रूपये की राशि जमा कर दी गयी है। इस परियोजना के लिए कुल 557 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं और कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेल मंत्री ने बताया कि बिहार में अब तक 98 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। राज्य में आठ वंदे भारत ट्रेनें, पांच अमृत भारत ट्रेनें और एक नमो भारत ट्रेन चल रही हैं। इसके साथ ही 218 प्लेटफॉर्म और अंडरपास भी बनाए गए हैं। अमृत भारत ट्रेनें प्रधानमंत्री मोदी की विशेष पहल हैं, जिनमें गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। ये ट्रेनें अब बिहार के कई हिस्सों से दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के लिए शुरू की गयी हैं।

'शरद और उद्धव की पार्टी लगातार भाजपा के संपर्क में', केसी त्यागी ने किया महाराष्ट्र में उलटफेर का दावा

एजेंसी

नई दिल्ली । जनता दल (यूनाइटेड) के दिग्गज नेता केसी त्यागी ने हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर अहम टिप्पणी की है। एक तरफ केसी त्यागी ने समाजवादी पार्टी सांसदों के मस्जिद जाने पर अखिलेश यादव का बचाव किया, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने का दावा किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने समाचार एजेंसी से बातचीत में शरद पवार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। साथ ही, उन्होंने बिहार में एसआईआर पर जारी राजनीति के बीच अपनी बात रखी। अखिलेश यादव दिल्ली में संसद भवन के पास बनी मस्जिद में समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ नजर आए थे। इस पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। हालांकि, केसी त्यागी का बयान बिल्कुल उलट आया है। उन्होंने कहा, ÷यह गलत नहीं है। उन्होंने कहा, रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवीवो इस मस्जिद के इमाम हैं। उन्हीं के निमंत्रण पर सपा के सांसद वहां चाय पीने गए

थे। इससे पहले भाजपा ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मस्जिद मीटिंग की जगह नहीं है। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर केसी त्यागी ने कहा, एसआईआर का आकलन चल रहा है। 97 प्रतिशत लोगों ने अपने नाम रजिस्टर्ड कराए हैं। एक महीने का समय राजनीतिक पार्टियों को दिया जाएगा, ताकि अपने नामों को सही से शामिल किया जा सके। शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। इस पर केसी त्यागी ने दावा करते हुए कहा, ÷महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। एनसीपी-एसपी और शिवसेना-यूबीटी, वह लगातार भाजपा के संपर्क में हैं। असल में देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन पर शरद पवार समेत कई नेताओं ने कॉफी टेबल बुक में उनकी प्रशंसा की थी। केसी त्यागी ने इस दौरान ममता बनर्जी की भाषाई आतंकवाद वाली टिप्पणी पर भी जवाब दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा, हिंदी को प्रमोट करना भाषाई आतंकवाद नहीं है। हम मराठी, बंगाली और तेलुगु समेत सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। इससे पहले, ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान कहा, भाजपा भाषाई आतंकवाद फैलाने का काम कर रही है।

झारखंड हाईकोर्ट के 17वें चीफ जस्टिस बने तरलोक सिंह चौहान, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

एजेंसी

रांची । झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने बुधवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। रांची के राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही वे झारखंड के 17वें चीफ जस्टिस बन गए। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी चीफ जस्टिस की नियुक्ति संबंधी वारंट को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश, झारखंड सरकार के कई मंत्री, महाधिवक्ता राजीव रंजन, जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के परिजन और राज्य सरकार के अधिकारी उपस्थित रहे। 9 जनवरी

1964 को हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू में जन्मे जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने शिमला के बिशप कॉटन से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। उन्होंने 1989 में हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकन के बाद सभी विधायी शाखाओं में गहरा अनुभव अर्जित किया। वह 2014 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश और फिर स्थायी न्यायाधीश बने। जस्टिस चौहान ने पर्यावरण कानून, बाल कल्याण और न्यायिक सुधारों में उल्लेखनीय कार्य किया। वे किशोर न्याय समिति, विधिक सेवा प्राधिकरण और हाईकोर्ट की कंप्यूटर एवं ई-कोर्ट समिति का नेतृत्व कर न्यायपालिका में डिजिटल परिवर्तन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश न्यायपालिका ने ई-फाइलिंग, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल न्यायिक प्रक्रियाओं में नए कीर्तिमान स्थापित किए। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस चौहान की नियुक्ति की अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति कार्यालय से 15 जुलाई को जारी की गई थी।

प्रसिद्ध नाटककार और रंगमंच निर्देशक रतन थियम का निधन

एजेंसी

मुम्बई। प्रसिद्ध नाटककार और रंगमंच निर्देशक रतन थियम का निधन हो गया। उन्हें बीती मध्य रात लगभग 1:30 बजे इम्फाल स्थित रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। भारतीय रंगमंच को नई पहचान देने वाले रतन थियम ने अपने करियर में कई ऐतिहासिक नाटकों का निर्देशन किया और भारतीय थिएटर को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया। उनके निधन से थिएटर जगत में शोक की लहर है। कलाकारों और रंगकर्मियों का कहना है कि रतन थियम के जाने से मंच ने एक अनमोल रत्न खो दिया है। गीतकार और प्लेबैक सिंगर स्वानंद किरकिरे सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारतीय रंगमंच के जादूगर-रतन थियम साहब! आपका जाना भारतीय रंगमंच के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पराकोटि का सौंदर्य बोध! भारतीयता - मणिपुर की संस्कृति में गहरे उतरी हुई आपकी जड़ों को साथ ले कर नितांत आधुनिक रंगमंच के रचयिता थियम साहब आप के रंगमंच का विश्व में कोई सानी नहीं! अलविदा सर। रतन थियम ने भारतीय रंगमंच की प्राचीन परंपरा को आधुनिक संदर्भ में जीवंत करते हुए नई दिशा दी। उन्होंने केवल नाट्य लेखन तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि रंगमंच के गहन विचार और दर्शन को भी मंच पर उतारा। 1987 से 1989 के बीच उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) में कई प्रभावशाली नाटकों का निर्देशन किया।

यूपी में निवेश लाने के लिए न्यू आउटरीच प्लान पर योगी सरकार का फोकस

एजेंसी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 35 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद योगी सरकार ने एक बार फिर नए निवेश प्रस्तावों के लिए कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने को लेकर योगी सरकार ने अब न्यू आउटरीच प्लान पर फोकस किया है। इसको अमल में लाने के लिए प्रदेश में निवेश की नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो की व्यापक रणनीति बनाई है। इसके तहत, चीन+1 रणनीति के तहत आयोजित होने वाले रोड शो के अतिरिक्त सितंबर-अक्टूबर 2025 में सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई, कतर और कनाडा में भी अंतरराष्ट्रीय रोड शो का आयोजन किया जाएगा। इन रोड शो का मुख्य उद्देश्य आगामी फरवरी 2026 में होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के लिए नए निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करना है। इसके लिए दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 की शुरुआत तक देश के अलग-अलग शहरों में में भी राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो किए जाएंगे,

ताकि घरेलू निवेशकों को भी जोड़कर समिट को नई ऊंचाई दी जा सके। नए निवेशकों के आउटरीच प्रोग्राम से पहले योगी सरकार नवंबर 2025 में पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी-5) का आयोजन करने जा रही है। इसमें 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि जैसे-जैसे जीबीसी-5 का समय नजदीक आएगा, यह आंकड़ा 10 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। अब तक प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से 12 लाख 10 हजार 274 करोड़ रुपए की 16 हजार 478 परियोजनाएं शामिल हुई हैं, जिनमें से चार लाख 33 हजार 528 करोड़ की 8 हजार 363 परियोजनाओं का वाणिज्यिक संचालन शुरू हो गया है। वहीं सात लाख 76 हजार 746 करोड़ रुपए की 8 हजार 115 परियोजनाएं जल्द संचालन पूरा करना शुरू कर देंगी। इन्वेस्ट यूपी ने न्यू आउटरीच नीति के तहत उभरते क्षेत्रों की पहचान की है। वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति अधिसूचित हो चुकी है। फुटवियर और चर्म उत्पाद नीति को जल्द अधिसूचित किया जाएगा। इसके साथ ही सतत विमान ईंधन (सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल) और निजी निवेश प्रोत्साहन नीति के ड्राफ्ट भी तैयार किए गए हैं। इन नीतियों में त्वरित निवेश प्रोत्साहन योजना, विस्तार/विविधीकरण हेतु छूट की सीमा और एमएसएमई से बड़े उद्यमों में रूपांतरण जैसे प्रावधान शामिल होंगे। आउटरीच प्लान के माध्यम से निवेशकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद, नई नीतियों का प्रोत्साहन और अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी के ज़रिए उत्तर प्रदेश को निवेश का ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी है। न्यू आउटरीच प्लान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर 15 दिन में एक घंटे की निवेशक राउंड टेबल बैठक कर रही है। साप्ताहिक आधार पर भी बैठकें की जा रही हैं ताकि निवेशकों के फीडबैक के आधार पर रणनीति को अपडेट किया जा सके। विदेश मंत्रालय (एमईए) के सहयोग से नई लीड्स सृजित करने के लिए भी उच्चस्तरीय बैठकें की जा रही हैं।

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने लूटपाट के आरोपी को दबोचा, पिस्टल और चोरी की बाइक बरामद

एजेंसी

नई दिल्ली। पूर्वी जिला की एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने एक मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी खेमचंद उर्फ समीर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पर पुलिस टीम पर हमला और लूट जैसे संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस ने आरोपित के पास से एक पिस्टल, जिंदा और खाली कारतूस तथा चोरी की बाइक बरामद की है। पूर्वी जिले के डीसीपी अभिषेक धनिया के अनुसार, 18 जुलाई की सुबह करीब 5:30 बजे एएसआई मोहम्मद कासिम और कॉन्स्टेबल कृष्णपाल आनंद विहार आईएसबीटी के पास सर्विस रोड नंबर 56 पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बाइक पर सवार तीन संदिग्धों को देखा और रुकने का इशारा किया। जिसपर संदिग्धों ने पुलिस टीम पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिस टीम से लाठियां छीनकर एएसआई कासिम के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई और उनका मोबाइल व पर्स लूटकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पुलिसकर्मी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और उनके बयान पर मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस ने जहरखुरानी गिरोह का किया भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम जिले की ऑपरेशन सेल ने जहरखुरानी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में लोनी, गाजियाबाद निवासी राजू (ड्राइवर), किशनगंज, बिहार निवासी शहजादा उर्फ गोल्टा, मोहम्मद आजाद और दरभंगा, बिहार निवासी मोहम्मद अताउल्लाह उर्फ गुड्डू शामिल है। इनके कब्जे से सात लोगों से लूटे गए मोबाइल फोन, अपराध में इस्तेमाल एक ऑटो और दस स्ट्रिप्स नींद की गोलियां व अन्य नशीली दवाएं बरामद की हैं। दक्षिण-पश्चिम जिले के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि अपराध नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सेल नियमित अभियान चला रही है। इसी के तहत इंस्पेक्टर हरि सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने जहरखुरानी के एक मामले की जांच करते हुए 30 किलोमीटर से अधिक एरीया की सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। तकनीकी सूचनाओं के आधार पर चोरी के मोबाइल की निगरानी की गई, जिससे अपराध में इस्तेमाल ऑटो का पता चला। डीसीपी के अनुसार चारों आरोपित चोरी का सामान बेचने और अगली वारदात की योजना बनाते समय पकड़े गए। आरोपितों का तरीका था कि वे अंतरराज्यीय यात्रियों, खासकर उप्र और बिहार जाने वालों को निशाना बनाते थे। वे पानी या ठंडे पेय में नींद की गोलियां मिलाकर पीड़ित को बेहोश कर देते और मोबाइल व कीमती सामान लूट लेते था।

वर्क-फ्रॉम-होम की नौकरी का झांसा देकर 17.49 लाख ठगी, चार गिरफ्तार

नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज में रहने वाले एक व्यक्ति से साइबर ठकों ने वर्क-फ्रॉम-होम की नौकरी का झांसा देकर 17.49 लाख रुपये ठग लिये। इस मामले की जांच करते हुए जिला साइबर थाना पुलिस ने इस साइबर ठगी को अंजाम देने वाले चार साइबर ठग सियापुर, यूपी निवासी अंकुर मिश्रा (22), राजगढ़, एमपी निवासी क्रतार्थ (21), भोपाल, एमपी निवासी विश्वास शर्मा (32) और शिवपुरी, एमपी निवासी केतन मिश्रा (18) को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चार मोबाइल फोन और चार सिम कार्ड बरामद किए गए, जो अपराध में इस्तेमाल हुए। दक्षिण पश्चिम जिले के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि 27 मई को एनसीआरपी पोर्टल पर एक दर्ज हुई थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि 23 मई को एक टेलीग्राम आईडी के जरिए उन्हें वेबसाइट रिव्यू करने के लिए 50 रुपये प्रति रिव्यू का लालच दिया गया। छोटे कार्यों के बाद, उन्हें बिटकॉइन खरीद-बिक्री के प्रीपेड टास्क में फंसाया गया। ठगों ने विभिन्न बहानों से उनसे बार-बार पैसे जमा करवाए, जिससे कुल 17.49 लाख रुपये की ठगी हुई। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक के नेतृत्व में गठित टीम ने ठगे गए रुपयों के मनी ट्रेल को ट्रैक किया। जांच में पता चला कि 5 लाख रुपये कोटक महिंद्रा बैंक के खाते में ट्रांसफर किए गए, जो अंकुर मिश्रा के नाम पर था। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर लखनऊ, भोपाल, शिवपुरी, और आगरा में छापेमारी कर एक-एक करके चारों आरोपितों को दबोचा गया।

ठगी के मामले में फरार आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लक्ष्मी नगर थाने में दर्ज 95 लाख रुपये की ठगी के मामले में फरार चल रहे आरोपित धर्मेन्द्र अग्रवाल को हरिद्वार के बैरागी कैंप से गिरफ्तार किया है। आरोपित खुद को एक बाबा रूप में प्रस्तुत कर समाज सेवा की आड़ में छिपा हुआ था। क्राइम ब्रांच के डीसीपी विक्रम सिंह के अनुसार शिकायतकर्ता बैलेश जैन ने नवंबर 2015 में आरोप लगाया कि धर्मेन्द्र अग्रवाल ने खुद को गाजियाबाद के प्रताप विहार स्थित एक रिहायशी प्लॉट का एकमात्र मालिक बताते हुए उसे बेचने की पेशकश की। दोनों के बीच 1.05 करोड़ में सौदा तय हुआ। जिसमें 95 लाख की राशि तीन चेकों के माध्यम से अग्रिम रूप से दी गई। 23 मई 2016 को प्रीत विहार एसडीएम ऑफिस में सेल एग्रीमेंट भी किया गया। जिसमें 10 लाख की शेष राशि प्लॉट की कब्जा और दस्तावेजों के हस्तांतरण के समय दी जानी थी। आरोपित ने यह दावा किया था कि संपत्ति पर कोई कानूनी रोक नहीं है। इसके बावजूद आरोपित ने बार-बार बहानेबाजी कर दस्तावेजों का हस्तांतरण नहीं किया और कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए देरी करता रहा। जब शिकायतकर्ता ने जुलाई 2022 में कानूनी नोटिस भेजा तो आरोपित ने जवाब देने की बजाय 40 लाख की और मांग की और न देने पर जान से मारने की धमकी दी।

दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश, जलभराव और ट्रैफिक जाम से जनजीवन अस्त-व्यस्त

एजेंसी

नई दिल्ली ।बुधवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में हुई भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम के कारण ऑफिस जाने वालों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश ने दिल्ली की रफ्तार को थाम लिया और कई इलाकों में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जिसमें मध्यम से भारी बारिश के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और आंधी की चेतावनी दी गई थी। नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद सहित दिल्ली के आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट लागू था।

वहीं, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जहां हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई।

भारी बारिश के कारण दिल्ली के

कई प्रमुख इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आईटीओ को जोड़ने वाले तीन प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल और धीमी गति के कारण भारी जाम लग गया। हालांकि, हवाई अड्डे के आसपास भारी बारिश के बावजूद उड़ान संचालन में कोई रुकावट नहीं हुई। मंगलवार, 22 जुलाई को हुई तेज बारिश के बाद प्रेस एनक्लेव रोड, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास अनुव्रत मार्ग, सैनिक फार्म्स, साकेत मेट्रो स्टेशन और मथुरा रोड के पास आश्रम जैसे इलाकों में पहले से ही जलभराव की स्थिति थी। बुधवार की बारिश ने हालात को और बिगाड़ दिया। एनएच-8, महरौली-गुड़गांव रोड, आईटीओ और लुटियंस दिल्ली जैसे प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम लगा। कई जगहों पर वाहन लंबी कतारों में फंस गए। नांगलोई से नजफगढ़ और दिल्ली-गाजियाबाद कॉरिडोर पर यात्रा में एक घंटे से ज्यादा का समय लग रहा था। जलमग्न फुटपाथ और कॉलोनियों में घुटनों तक पानी भरने से लोग परेशान हो गए।

नाराज यात्रियों ने सोशल मीडिया पर सड़कों की हालत, जलभराव और ट्रैफिक जाम की तस्वीरें और वीडियो साझा किए। लोगों ने प्रशासन से जलजमाव की समस्या को हल करने और सड़क व्यवस्था में सुधार की मांग की है।

हत्या के प्रयास में दो वांछित आरोपित गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। हत्या के प्रयास के मामले में फरार दो आरोपितों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गएआरोपितों की पहचान वाजीरपुर निवासी कृष्ण उर्फ नारायण (32) और जहांगीरपुरी निवासी सुमित उर्फ छव्वा उर्फ अभिषेक (27) के रूप में हुई है।आरोपित दो अलग-अलग हत्या के प्रयास के मामलों भरत नगर और जहांगीर पुरी में वांछित थे। महीनों से गिरफ्तारी से बचते फिर रहे थे। क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम के अनुसार भरत नगर थाने में नौ जुलाई की रात परिवहन कर्मी फिरोज पर मच्छी पुल, वजीरपुर के पास कृष्ण उर्फ नारायण और उसके साथियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। नारायण ने फिरोज के सीने पर गोली चलाई। घटना के वक्त पीड़ित दीवार फांदकर किसी तरह जान बचाकर भागा। अन्य आरोपितो ने तलवार से हमला करने की कोशिश की। उक्त मामले में स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसी क्रम में जहांगीर पुरी थाने में पांच फरवरी को सुमित उर्फ छव्वा उर्फ अभिषेक ने हाथी वाला पार्क के पास पीयूष को सीने में गोली मारी। यह हमला पुरानी रंजिश के चलते किया

गया और इसमें उसके दो साथी भी शामिल थे।डीसीपी के अनुसार दोनों मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चौखंडी क्षेत्र में छापेमारी कर दोनों अपराधियों को दबोचा। जांच में पता चला है कि कृष्ण उर्फ नारायण, अपने पिता कुदु स्वामी (घोषित अपराधी) के नाम से गैंग संचालित करता है। उसका गैंग फिरोज के गिरोह से रंजिश रखता है, और इन दोनों गुटों के बीच कई बार गोलीबारी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

लंबित विधेयक की समयसीमा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को भेजा नोटिस

एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय करने के महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि अगस्त में इस मामले पर विस्तृत सुनवाई शुरू होगी।

यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब इस साल अप्रैल में तमिलनाडु के 10 विधेयकों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसके बाद कोर्ट न केवल सभी विधेयकों को परित करार दिया था, बल्कि विधेयक पर फैसले की समय सीमा तय कर दी थी। यह सीमा राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए तय की गई थी। कोर्ट ने कहा था, जब राज्य विधानसभा की ओर से पास बिल को गवर्नर आगे विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजें, तो उन्हें तीन महीने में उस पर फैसला लेना होगा। इस तरह कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए तीन महीने की समय सीमा निर्धारित

यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब इस साल अप्रैल में तमिलनाडु के 10 विधेयकों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

की थी।इस फैसले को कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव के रूप में देखा गया। इसके मद्देनजर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा, जिसके आधार पर संविधान पीठ गठित की गई। यह पीठ विधेयक पर फैसले की समय सीमा और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या पर विचार करेगी। इसी साल 8 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा 2023 में 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित रखने के कदम को अवैध और गलत करार दिया था। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने फैसला सुनाया था कि विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, राज्यपाल के पास विधेयक को रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। उन्हें अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करना होता है।

किरेन रिजिजू का हमला, कहा- देश की टैक्स मनी को हंगामा करके विपक्ष कर रहा बर्बाद

एजेंसी

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों के लगातार हंगामे के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने विपक्ष पर 'टैक्स का पैसा बर्बाद करन' और मौजूदा सत्र के दौरान जानबूझकर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि बैठक में ये तय किया गया कि सबसे पहले 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा होगी। इसके लिए समय भी तय किया गया है। एक साथ सारे मुद्दे पर चर्चा संभव कैसे है? फिर भी, सहयोग करने के बजाय, वे तख्तियां लेकर आए और सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाला। ये हर समय नियम के विरुद्ध तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हैं, यह निंदनीय है। जबकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि पोस्टर, बैनर लेकर सदन में नहीं आएंगे। उन्होंने आगे कहा, 'पोस्टर-बैनर लेकर सदन को बाधित करना आपत्तिजनक है, वह (विपक्ष)

चर्चा की मांग कर रहे हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। फिर वह सदन क्यों नहीं चलने दे रहे? यह दोहरा मापदंड गलत है। अगर आप चर्चा चाहते हैं, तो ये हंगामा नहीं करें। सरकार ने बार-बार कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन ये हंगामा क्यों कर रहे हैं, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। देश की टैक्स मनी को आप हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं। इसका जवाब देना पड़ेगा। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथी दो दिन से हंगामा कर रहे हैं। मैं इसका खंडन करना चाहता हूं।'संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। विपक्ष की ओर से बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), पहलगाम हमले और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग की गई और जमकर नारेबाजी हुई। जिसके बाद हंगामे की वजह से सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस : आरोपियों की रिहाई के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

एजेंसी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 24 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 12 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई तुरंत लगाने पर सहमति जताई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की थी। मेहता ने कहा कि राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर तुरंत सुनवाई जरूरी है, क्योंकि यह एक गंभीर मामला है और इसमें कुछ अहम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का विचार जरूरी है।बॉम्बे उच्च न्यायालय ने

11 जुलाई 2006 के मुंबई विस्फोट मामले में 12 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें से पांच को मृत्युदंड और सात अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और एस चंदक की पीठ ने फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों को तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया। यह फैसला जांच एजेंसियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। न्यायमूर्ति किलोर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अभियोजन पक्ष पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह तक साबित नहीं कर सका कि इस अपराध में किस प्रकार के बम इस्तेमाल किए गए थे। बता दें कि वर्ष 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। इस मामले में 12 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट की ओर से इन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने विशेष टाडा न्यायालय की ओर से दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें से 5 को मृत्युदंड और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। यह फैसला 19 साल बाद आया है। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस चांडक की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों में कोई ठोस आधार नहीं था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दया। यह मामला 11 जुलाई 2006 का है, जब मुंबई की लोकल ट्रेनों में शाम के समय मात्र 11 मिनट के अंदर सात अलग-अलग जगहों पर सीरियल बम धमाके हुए थे।

चाकू से हमला कर नाबालिगों ने ली युवक की जान

एजेंसी

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी जिले के वेलकम थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के दौरान नाबालिगों ने एक युवक की चाकू घोपकर हत्या कर दी गई। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है। जांच में मृतक की पहचान जनता मज़दूर कॉलोनी निवासी मुस्तकीन (39) के रूप में हुई है। वेलकम थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर तीन नाबालिगों को पकड़ा है।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई की रात करीब 11:21 बजे थाना वेलकम में एक चाकूबाजी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पूछताछ में स्थानीय लोगों ने बताया कि घायल को पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में मृतक की पहचान मुस्तकीन के रूप में हुई। इधर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना के कुछ घंटे बाद ही तीन नाबालिगों को पकड़ा। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि मृतक मुस्तकीन और इन नाबालिगों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान आरोपितों ने पीड़ित के ऊपर चाकू से हमला किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

कांवड़ियों का सीएम रेखा गुप्ता ने किया स्वागत, महिलाओं के छुए पैर

एजेंसी

नई दिल्ली । सावन महीने में भोले की भक्ति का रंग दिल्ली पर भी चढ़ा है। राष्ट्रीय राजधानी में इस बार कांवड़ियों के लिए भव्य कार्यक्रम रखे गए हैं, जहां एक कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थित बाबा श्यामगिरी मंदिर में रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ लाने वाली महिलाओं का तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया और शिवभक्तों पर फूलों की वर्षा की। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा, शाहदरा के विधायक संजय गोयल और दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष सत्या शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कांवड़ लेकर आई महिला श्रद्धालुओं के माथे पर तिलक लगाया और उनके पैर छुए। इस बार दिल्ली में सरकार की ओर से 374 कांवड़ शिविर लगाए गए हैं। सभी शिविर कैंपों में सरकार की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा,

÷दिल्ली शिवभक्ति में सराबोर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ बाबा श्यामगिरी मंदिर पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत का सौभाग्य मिला। तिलक लगाकर अभिनंदन करते हुए दिल्ली सरकार ने शिवभक्तों को सम्मान और सेवा का संदेश दिया। ये यात्रा सनातन की शक्ति और श्रद्धा का उत्सव है। शिवमय दिल्ली का हर कोना भोलेनाथ की महिमा से गूंज रहा है।' इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा परिसर में 'नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन' (एनईवीए) कक्ष का दौरा किया और आगामी मानसून सत्र के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। यह प्रशिक्षण 21 से 23 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य कागज रहित विधायी कार्यप्रणाली को सुदृढ़ और सहज बनाना है।

राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात

जेंसी

नई दिल्ली। नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात की और उनके साथ चर्चा की। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आज कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन, नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात और चर्चा की। जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों की रक्षा और प्रदेश के हित के लिए कांग्रेस पूरी तरह से समर्पित है। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। इससे पहले दिन में जम्मू-कश्मीर के कांग्रेसी नेताओं ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने की मांग की गई और क्षेत्र में भाजपा द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों के अलोकतांत्रिक, सत्तावादी और असंवैधानिक दमन की कड़ी निंदा की गई। इसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, कांग्रेस विधायक दल के नेता जीए मीर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख प्रभारी महासचिव डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने

किया। कांग्रेस नेतृत्व ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में इन मुद्दों को उठाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली आए जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरा समर्थन दिया। जम्मू-कश्मीर से 500 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता दिल्ली पहुंचे और 'दिल्ली चलो' और हमारी रियासत हमारा हक जैसे नारे लगाए।

सभी नागरिकों को हर साल हेल्थ चेकअप का कानूनी अधिकार मिलेः राघव चड्ढा

एजेंसी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सरकार से मांग की है कि प्रत्येक नागरिक को हर साल स्वास्थ्य जांच का कानूनी अधिकार दिया जाए। राज्यसभा के मानसून सत्र में राघव चड्ढा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद देश में हार्ट अटैक और अन्य बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने संसद में यह मांग रखी कि हर नागरिक को हर साल हेल्थ चेकअप कराने का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। कोविड के बाद दिल की बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। अगर बीमारियों का समय रहते पता चल जाए, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कई विकसित देश अपने नागरिकों को हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा देते हैं, जिसका खर्च सरकार उठाती है। फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? राघव चड्ढा ने कहा, इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को नियमित जांच की सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वे गरीब हों या अमीर। उन्होंने एक नारा दिया–जांच है तो जान है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब हाल ही में कई

युवा और स्वस्थ दिखने वाले लोगों में भी अचानक दिल का दौरा, स्ट्रोक और अन्य गंभीर बीमारियां देखी गई हैं।हर साल होने वाली 70 प्रतिशत से ज्यादा मौतें दिल से जुड़ी बीमारी, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और फेफड़ों की बीमारी आदि जैसी गैर-संचारी बीमारियों के कारण होती हैं। अगर इन बीमारियों की नियमित जांच के साथ-साथ ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों के उपचार के लिए 30 साल और उससे ज्यादा की उम्र के सभी लोगों की जांच करना है। यह जांच अभियान आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर चलाया गया और इसने अपने 89.7 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा भी किया।

अमित शाह गुरुवार को नई दिल्ली में 'राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025' का अनावरण करेंगे

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को नई दिल्ली में 'राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025' का अनावरण करेंगे। नई सहकारिता नीति 2025-45 तक आगामी दो दशकों के लिए भारत के सहकारी आंदोलन में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को अटल अक्षय ऊर्जा भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारिता नीति के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के सदस्य, सभी राष्ट्रीय सहकारी संघों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) और वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। नई सहकारिता नीति 2025-45 तक आगामी दो दशकों के लिए भारत के सहकारी आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में, नई सहकारिता नीति 2025 का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और आधुनिक बनाने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर एक रोडमैप बनाकर सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना है। इससे पहले वर्ष 2002 में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी की गई थी, जिसमें सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक आधारभूत रूपरेखा दी गई थी। पिछले 20 वर्षों में वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के कारण समाज, देश और विश्व में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए नई नीति बनाना आवश्यक हो गया था, ताकि सहकारी संस्थाओं को वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अधिक सक्रिय और उपयोगी बनाया जा सके और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका मजबूत हो सके। राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को समावेशी बनाने, उनका पेशेवर तरीके से प्रबंधन करने, उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने और विशेष रूप से ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर सृजित करने में सक्षम बनना है।

संपादक की कलम से

भारत को एक राष्ट्र के रूप में जल सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी

डे जीरो–एक ऐसा शब्द है जो अब केवल एक संभावित आपदा नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक का प्रतीक बन चुका है। यह शब्द पहली बार 2018 में वैश्विक स्तर पर चर्चा में तब आया जब दक्षिण अफ्रीका का कैपटाउन शहर पानी की आपूर्ति पूरी तरह समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। 'डे जीरो' वह दिन होता है जब शहर के सभी नल बंद कर दिए जाते हैं, और नागरिकों को सार्वजनिक वितरण केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़े होकर सीमित मात्रा में पानी प्राप्त करना पड़ता है। कैपटाउन में यह सीमा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 25 लीटर निर्धारित की गई थी। हालांकि इस संकट का कारण केवल जलवायु परिवर्तन या वर्षा की अनिश्चितता नहीं था–यह दशकों की नीति विफलता, शहरों का अति-विस्तार, परंपरागत जल स्रोतों की उपेक्षा और जल प्रबंधन में बड़ी खामियों का संयुक्त परिणाम था।

कैपटाउन ने कड़ी नीतियों और नागरिक सहभागिता से इस आपदा को कुछ समय के लिए टाल दिया है। लेकिन पानी की गंभीर किल्लत की आहट अब भारत के दरवाजे तक होने लगी है। भारत जैसे देशों में, जहां जनसंख्या अत्यधिक है, शहरीकरण अनियंत्रित है, और भूजल दोहन पर कोई स्पष्ट नियंत्रण नहीं–डे जीरो अब भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि एक आसन्न यथार्थ है।

बेंगलुरु, जिसे कभी ह्यझीलों का शहरह्ल कहा जाता था, आज जल संकट के सबसे भीषण दौर से गुजर रहा है। यहां की अधिकांश झीलें अब या तो कचरा डंपिंग साइट बन चुकी हैं या अवैध निर्माण की भेंट चढ़ गईं। भूजल स्तर हर वर्ष 10-12 मीटर की दर से नीचे जा रहा है। बेंगलुरु में डे जीरो की आंशिक झलक तब देखने को मिली जब पूरे शहर में टैंकर के पानी पर निर्भरता बढ़ी।

चेन्नई भी 2019 में डे जीरो जैसे संकट का सामना कर चुका है जब उसके चारों जलाशय सूख गए थे। वहीं दिल्ली की स्थिति भी बेहतर नहीं–शहर की मुख्य जलधारा यमुना प्रदूषण और अतिक्रमण की शिकार है, जबकि भूजल स्तर अत्यधिक गंभीर श्रेणी में जा चुका है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के 21 बड़े शहरों में जलापूर्ति पूरी तरह समाप्त हो सकती है।

पानी के मामले में हरियाणा की स्थिति भी चिंताजनक है। धान,गन्ने जैसी अत्यधिक जल-खपत वाली फसलों का विस्तार, सिंचाई तकनीकों का अल्प उपयोग और नगण्य वर्षा जल संचयन ने भूजल अंधाधुंध तरीके से समाप्त कर दिया। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार हरियाणा के 85 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों में भूजल स्तर खतरनाक स्तर पार कर चुका है।

भारत में जल संकट के लिए जिम्मेदार केवल वर्षा की अनियमितता नहीं है, बल्कि जल निकायों पर अतिक्रमण, नीति असंगति, शहरी अपशिष्ट का जल स्रोतों में मिलना और लोगों में जल बचत के प्रति उदासीनता जैसे कारक भी उतने ही उत्तरदायी हैं।

जल संकट से निपटने के लिए कई योजनाएं तो बनाई गईं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कागजी आंकड़ों तक ही सीमित रह गया। मसलन, जल जीवन मिशन को सिर्फ ह्यहर घर नलह्ल तक सीमित समझा गया, जबकि उसका मूल उद्देश्य स्थानीय जल स्रोतों का सशक्तीकरण और सामुदायिक सहभागिता के जरिए जल आत्मनिर्भरता था।

इस स्थिति से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। जल को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानकर नागरिक सहभागिता पर बल देना होगा। जल संरक्षण को जीवनशैली में लाना होगा झ्र जैसे कैपटाउन में लोगों ने बर्तनों में नहाने का पानी जमा कर पौधों को सींचा, हाथ धोते समय नल बंद करना सीखा और शौचालयों में रिसाइकल पानी का प्रयोग शुरू किया।

भारत में भी प्रत्येक इमारत में वर्षा जल संचयन अनिवार्य करना चाहिए, जिसे स्थानीय निकाय सख्ती से लागू करें। भूजल का मापन, नियमन और पुनर्भरण एक समर्पित मिशन के तहत चलाया जाए। जल जीवन मिशन को स्थानीय स्रोतों को पुनर्जीवित करने और जल संरक्षण पर केंद्रित करना होगा। शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट की जगह परकोलेशन पिट्स, बायोस्वेल्स और हरित क्षेत्र बढ़ाने होंगे ताकि वर्षा जल भूमि में जज्ब हो सके। पानी की कीमत समझना और उपभोग पर नियंत्रण लाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए स्लैब आधारित मूल्य निर्धारण, जहां न्यूनतम जरूरतों के बाद अतिरिक्त खपत पर उच्च शुल्क लगे, एक व्यावहारिक नीति हो सकती है। इससे पानी का विवेकपूर्ण उपयोग प्रोत्साहित होगा। वहीं, तकनीकी नवाचार जैसे जल रिसाव की स्मार्ट निगरानी, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और समुद्री जल से मीठा पानी बनाने की प्रक्रिया को प्रमुखता दी जानी चाहिए। चेन्नई ने समुद्री जल शोधन संयंत्र की ओर कदम बढ़ाया है, और यह उन तटीय शहरों के लिए प्रेरणा हो सकता है जहां भूजल या वर्षा जल अपर्याप्त है।

मराठी बोलना गर्व की बात, लेकिन हिन्दी से घृणा क्यों ?

अजय जैन 'विकल्प'

अपनी स्थापना से ही भारत विविधताओं का देश बना हुआ है और भाषा इसकी सबसे खूबसूरत विशेषताओं में से एक है। इसलिए यहाँ अनेकता के बावजूद एकता है, चाहे फिर कोई भी मुद्दा हो, यानी कभी अपने को श्रेष्ठ बताकर किसी अन्य को बुरा नहीं कहा गया, किन्तु इस देश के राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई में फिलहाल यही बुरा देखा जा रहा है, जो अनुचित है और देश की भाषाई एकता के लिए घातक भी है।

मुम्बई न केवल आर्थिक राजधानी है, बल्कि भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों का संगम स्थल भी है। इस महानगर में मराठी का बोलबाला होना स्वाभाविक है, यह इस मिट्टी की आत्मा है, लेकिन आज एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभर रही है:हिन्दी के प्रति अघोषित घृणा दिख रही है, जिसके पीछे असहिष्णुता, राजनीतिक विद्वेष एवं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने की अजीब मानसिकता है। मराठी को सम्मान देने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। आपत्ति तब होती है, जब इस सम्मान के नाम पर हिन्दी को हाशिए पर धकेला जाता है, हिन्दी भाषियों को 'बाहरी' करार दिया जाता है, और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। यह केवल भाषाई टकराव नहीं, एक गहरी राजनीतिक साजिश है, जिसे समझना, उजागर करना और विरोध करते हुए हिन्दी के लिए खड़े रहना बहुत आवश्यक है। यह समझना होगा कि मराठी स्वाभिमान की भाषा है, लेकिन हिन्दी के प्रति संकीर्णता सही नहीं है। मराठी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि सभ्यता, इतिहास और गौरव है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, लोकमान्य तिलक और बाल गंगाधर तिलक आदि महापुरुषों ने मराठी को जनचेतना और क्रांति का माध्यम बनाया, तो कैद में रहते हुए भी राष्ट्रीय एकता के लिए वीर विनायक सावरकर ने हिन्दी कविताएं रचीं एवं हिन्दी सिखाई। आज भी महाराष्ट्र में मराठी साहित्य, नाटक, संगीत और संस्कृति की धारा बह रही है।

मराठी बोलना, मराठी में गर्व करना, उस विरासत को आगे बढ़ाना हर मराठीभाषी का हक और कर्तव्य है मगर जब यह गर्व दूसरों की भाषा के प्रति घृणा में बदल जाता है, तो यह स्वाभिमान नहीं, संकीर्णता बन जाता है।

सबको समझना पड़ेगा कि हिन्दी एकता का सेतु और मुम्बई का मौन आधार है। हिन्दी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो उत्तर भारत से लेकर भारत के कोने-कोने तक संवाद का माध्यम है। मुम्बई जैसे महानगर में हिन्दी केवल उत्तर भारतीयों की नहीं, बल्कि लाखों मराठी, गुजराती, बिहारी, तमिल, मलयाली और बंगालियों के भी दैनिक संवाद की भाषा बनी हुई है।

मुम्बई यानी बॉलीवुड सहित रेडियो, टेलीविजन, विज्ञापन, सेवा क्षेत्र और मीडिया के अधिकतर प्रमुख उद्योग हिन्दी के दम पर खड़े हैं। यही नहीं, लाखों मेहनतकश मजदूर, वाहन चालक, नौकर, घरेलू कामगार, उद्घोषक, पत्रकार और कलाकार भी हिन्दी के माध्यम से ही रोजी-रोटी व पहचान प्राप्त करते हैं, तो बड़ा सवाल है कि इस हिन्दी से इतनी घृणा क्यों, मारपीट क्यों, प्रदर्शन क्यों...?

स्थानीय राजनीतिक कारण देखें तो पता चलता है कि 'मराठी बनाम हिन्दी' की कृत्रिम खाई बनाई गई है, क्योंकि उसी से तो सत्ता प्राप्ति का मार्ग मिलेगा। भाषा का यह संघर्ष अचानक नहीं पनपा है, बल्कि यह कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों की योजनाबद्ध रणनीति का परिणाम है। 'मराठी मानुस' के नारे के पीछे वर्षों से एक 'अपराध-बोध' और 'भय' को बोया गया, कि हिन्दी भाषी मुम्बई को 'हड़प' रहे हैं, जबकि सत्यता इससे अलग है और धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हिन्दी बोलने वाला अपना काम कर रहा है, तो मराठी एवं अन्य भाषा बोलने वाला अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, इनमें कोई झगड़ा नहीं है। राज्य और मुम्बई को निगलने के ऐसे विचार न केवल झूठे हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा हैं, क्योंकि मुम्बई की आत्मा में तो हिन्दी हमेशा रही है। १९५० के दशक में भी जब बम्बई राज्य बना था, तब भी हिन्दीभाषी इसके विकास में बराबरी से सहभागी थे।

हिन्दी को 'बाहरी भाषा' कहने वाले यह भूल जाते हैं कि संविधान में यह राजभाषा घोषित है और इसे पूरे भारत में समान सम्मान प्राप्त है। ऐसा भी लगता है कि असल डर हिन्दी से नहीं, बल्कि उस जनसांख्यिकी बदलाव से है, जो उत्तर भारत से आए श्रमिकों और युवाओं के कारण मुम्बई में हो रहा है। बेरोजगारी, शिक्षा में गिरावट और स्थानीय युवाओं को नौकरियों नहीं मिलने का दोष भी हिन्दी भाषियों पर डाल देना आसान बहाना बन गया है, लेकिन इसका उचित समाधान खोजने की अपेक्षा हिन्दी को रोककर गुंडागर्दी करना कहाँ से सही हो गया है ? क्या हिन्दी भाषियों को निकाल देने से, हिन्दी नहीं बोलने देने से, राजनीति करने से एवं सिर्फ मराठी की जिद लगाने से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा ? राज्य तरक्की कर लेगा, हिन्दी और मराठी का स्नेह बना रहेगा ?

उत्तर साफ है-नहीं, क्योंकि विकास की कुंजी भाषाओं को सीमित करने में नहीं, बल्कि उन्हें सर्वव्यापी व समावेशी बनाने में है। राजनीति के चक्कर में यह भूलना घातक है कि हिन्दी को अपमानित करना आसान है। वास्तव में यह संविधान का अपमान है, क्योंकि संविधान की धारा ३४३ हिन्दी को राजभाषा घोषित करती है। अनुच्छेद १९ हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, तो कोई भी राज्य, नगर या संस्था किसी भाषा विशेष को किसी को बोलने से कैसे रोक सकता है। मुम्बई में हिन्दी बोलने वाले पर तंज कसना, दुकानों के बोर्ड बदलवाना या हिन्दी में सेवा देने से इनकार करना सीधे तौर पर संविधान का सीधा उल्लंघन यानी राष्ट्रद्रोह है।

मुम्बई में हिन्दी का विरोध करने वालों एवं भाषा के बँटवारे पर मौन रहने वालों को भाषाई सौहार्द के उदाहरण दक्षिण भारत से सीख लेनी चाहिए। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपनी भाषाओं को मजबूत किया, लेकिन कभी हिन्दी को दुश्मन नहीं बनाया। बेंगलुरु जैसे शहर में भी कन्नड़ प्रमुख है, लेकिन हिन्दी स्वीकार है। वहाँ के लोग हिन्दी सीखते हैं, सिखाते हैं और साथ रहते हैं।

मुम्बई, जो देश का सबसे बड़ा समावेशी शहर कहलाता है, वहाँ से हिन्दी फिल्म और टी.वी. उद्योग निकाल दिया जाए, तो कल्पना करें कि क्या बचेगा ? अगर हिन्दी बोलने वाला अपने ही देश में पराया महसूस करे, तो यह केवल शर्मनाक नहीं, बड़ा जहर है।

सबको इस बात को महसूस करना होगा कि भाषाई टकराव से कुछ नहीं सधेगा। मराठी और हिन्दी दोनों समृद्ध भाषाएं हैं। दोनों में साहित्य, संस्कृति, ज्ञान और इतिहास की गहराइयाँ हैं। इसलिए कुछ सकारात्मक कदम एवं उदारता लेकर विद्यालयों में मराठी और हिन्दी दोनों को सम्मानजनक स्थान दिया जाए। सार्वजनिक बोर्डों में मराठी प्रमुख हो, लेकिन हिन्दी को न हटाया जाए। सरकार ऐसे कार्यक्रम चलाए, जो भाषाई सौहार्द को बढ़ावा दें। यानी नेता 'वोट बैंक' के लिए भाषा को हथियार न बनाएं।

राजनीति से पनपाए गए इस विवाद का समाधान बनाम निष्कर्ष यही है कि मुम्बई की आत्मा मराठी और हिन्दी का संगम है, यानी मुम्बई केवल मराठी या हिन्दी की नहीं, बल्कि पूरे भारत की है। जैसे कश्मीर भारत का स्वर्ग है, ऐसे ही महाराष्ट्र और मुम्बई का असली सौंदर्य विविधता-अनेकता में है। हिन्दी से घृणा करके हम न तो मराठी को मजबूत कर सकते हैं, न मुम्बई को।

मराठी और हिन्दी २ भाषाएं नहीं, २ आत्माएं हैं-जिन्हें जोड़कर ही भारत एकता और शक्ति की मिसाल बनेगा। कारण कि किसी भी भाषा से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन किसी भाषा से घृणा करना अपने ही देश और उसके नियम-कायदों से घृणा करने जैसा है।

यह भी तय है कि मुम्बई और राज्य के अन्य हिस्सों में मराठी बनाम गैर-मराठी भाषा विवाद को लेकर चल रहे राजनीतिक और सामाजिक तनाव, प्रदर्शन, गुंडागर्दी और जबरदस्ती से भाषा एवं क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा हल नहीं होगा, बल्कि इससे आमजन के बीच विश्वास घटकर विष फैलेगा। बेहतर यह है कि सरकार और सभी को राज्य-देश हित में इस घमासान को टालते हुए देशप्रेम दिखाकर दोनों भाषा का सम्मान स्वीकारना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद

भारत में मुख्यधारा का मीडिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह मानते हुए अब सकारात्मक रवैया अपनाने लगा है, खासकर तब, जबकि इसमें किसी भी तरह भाजपा का हित जुड़ा हो। प्रधानमंत्री बनने से पहले दिल्ली में कॉलेज छात्रों को दिए एक भाषण में अपनी सकारात्मक सोच का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा था कि वे गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, इस सवाल पर कहते हैं कि गिलास पूरा भरा है, जो खाली दिख रहा है, वहां हवा भरी है। तो बस तब से देश में ऐसे ही हवा-हवाई माहौल चल रहा है। कुछ रहे न रहे, बस सब चंगा सी की उम्मीद पर देश को चलाया जा रहा है। मीडिया भी तथ्यों को न देखकर हवा-हवाई बातों को बढ़ा रहा है। जैसे गुरुवार को मीडिया ने इस बात को जोर-शोर से चलाया कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग की बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की कवायद पर शीर्ष अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन ये हवा से आधे भरे गिलास का उदाहरण है। असल बात ये है कि शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से साफ तौर पर कहा है कि वह जिन 11 दस्तावेज की मांग मतदाताओं से कर रहा है, उसमें आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि आप नागरिकता के मुद्दे पर क्यों जा रहे हैं, यह गृहमंत्रालय का विषय है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों और तर्कों के आधार पर

ही सुनवाई होने दी और उसकी अहम टिप्पणियां भी इन्हीं के आधार पर थीं। सुप्रीम कोर्ट न पूरी तरह चुनाव आयोग के पक्ष में दिखा, न उसने याचिकाकताओं की तरफ कोई पक्षपात दिखाया, बल्कि उसकी तटस्थता साफ नजर आई, फिर भी मीडिया में चलाए जा रहे शीर्षक यह भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बिहार में जिस मुद्दे को लेकर 9 जुलाई को विपक्ष ने इतना बड़ा हल्ला बोल किया, उस मुद्दे पर विपक्ष को अदालत में झटका मिला है। जबकि ऐसा नहीं है। गौरतलब है कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (एसआईआर) की कवायद शुरू की और इसके लिए केवल एक महीने का ही वक्त मतदाताओं को दिया कि वे अपने नागरिक होने का प्रमाण खुद ही पेश करें। आयोग ने 11 दस्तावेज की सूची जारी की और कहा कि इनमें से किसी को पेश करने पर ही किसी का नाम मतदाता सूची में आएगा, अन्यथा काट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं से खुद के नागरिक होने का सबूत मांगा, जबकि इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा कार्ड को मान्यता नहीं दी, जबकि करोड़ों गरीबों के पास यही सबसे सुलभ पहचानपत्र होते हैं और इन्हें भी सरकार ही जारी करती है। इस फैसले को लोकतांत्रिक अधिकार पर सीधा हमला करते हुए चुनाव आयोग के समक्ष विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया था, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला तो विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद करवाया और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए। 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अलावा राजद सांसद मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के के. सी. वेणुगोपाल, राकांपा (शरद पवार गुट) की सुप्रिया सुले, भाकपा के डी. राजा, सपा के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के अरविंद सावंत, झामुमो के सरफराज अहमद, और भाकपा (माले) के दीपंकर भट्टाचार्य, इन सभी ने शीर्ष अदालत से चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा सकता है, लेकिन इस विशेष गहन पुनरीक्षण में कई समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लगभग 7.9 करोड़ नागरिकों को कवर करेगी, और इसमें वोटर आईडी और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। याचिकाकेताओं ने कहा कि वोटर लिस्ट का रिवीजन मतदाताओं पर अपनी नागरिकता साबित करने का दबाव डालता है जबकि यह काम चुनाव आयोग का है।

उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि वह 30 दिनों में पूरी मतदाता सूची का रिवीजन करेगा। इस मामले में गुरुवार को पहली सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने मामले में सुनवाई की। बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा कि आधार कार्ड को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। जिस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने जवाब दिया कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। तब जस्टिस धूलिया ने कहा, 'लेकिन नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र है। इस पर चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया कि आयोग को अनुच्छेद 326 के तहत अधिकार प्राप्त हैं। वहीं जस्टिस बागची ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर आपका निर्णय यह है कि 2025 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज व्यक्ति को भी मताधिकार से वंचित किया जाए, तो उस व्यक्ति को अपील करनी होगी, पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा और अंततः आगामी चुनाव में मतदान का अधिकार छिन जाएगा। आप मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच कर सकते हैं ताकि गैर-नागरिक सूची में न रहें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप यह कार्य प्रस्तावित चुनाव से कुछ ही महीने पहले शुरू करते हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन आयोग को तीन दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड स्वीकार करने का सुझाव दिया है।

सांप: रहस्य नहीं, समझ का विषय हैं वे

सांपों को लेकर मानव समाज में आदिकाल से ही रहस्य, भय और अंधविश्वास जुड़ते चले आए हैं। विशेषकर भारत जैसे देश में सांप केवल एक जीव नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और प्रतीकों से जुड़ा हुआ नाम है। नाग देवता की पूजा से लेकर लोक कथाओं, परंपराओं और फिल्मों तक, सांप को कभी आराध्य रूप में तो कभी खलनायक के रूप में देखा गया है। लेकिन इस भावनात्मक और काल्पनिक दृष्टिकोण से अलग, अगर हम सांपों को वास्तविकता और वैज्ञानिक समझ के साथ देखें, तो एक बिलकुल अलग तस्वीर सामने आती है एक ऐसी तस्वीर जिसमें सांप न भयावह हैं, न रहस्यमयी, बल्कि प्रकृति की एक अद्भुत और आवश्यक रचना हैं। धरती पर सांपों की लगभग 3,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में करीब 300 प्रजातियाँ मौजूद हैं। इनमें से भी केवल कुछ ही प्रजातियाँ विषैली होती हैं, जैसे कि कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर जिन्हें ह्यबिग फोरह्ल कहा जाता है। शेष अधिकांश सांप निरपराध और मानव के संपर्क से बचने वाले जीव हैं। लेकिन डर और अज्ञानता के चलते अक्सर हर सांप को खतरनाक समझा जाता है और उन्हें मार दिया जाता है, चाहे वह विषैला हो या नहीं।

वास्तव में, सांप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद जरूरी हैं। वे खेतों और घरों में चूहों व अन्य कीटों की संख्या नियंत्रित करते हैं, जो फसलों और खाद्यान्न को नुकसान पहुँचाते हैं। यदि सांप न हों, तो यह असंतुलन खाद्य श्रृंखला में भारी विघटन ला सकता है। उनके बिना हमारी जैव विविधता अधूरी है। सांपों का शरीर बिना पैरों के होते हुए भी अत्यंत लचीला, तेज और पर्यावरण के अनुकूल होता है। वे जंगलों, खेतों, रेगिस्तानों, पर्वतों और यहाँ तक कि बर्फीले इलाकों में भी जीवित रह सकते हैं। उनकी खाल समय-समय पर झड़ती है, जिसे कुछ परंपराओं में नवजीवन या पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। भारतीय परंपरा में शेषनाग, वासुकी और अनंत जैसे नागों की कथाएँ आज भी जीवंत हैं। भगवान विष्णु के शयन के आसन से लेकर शिव के गले में लिपटे वासुकी तक, सांपों को ईश्वर से जोड़कर देखा गया है। नागपंचमी जैसे पर्व, नाग मंदिरों की स्थापना और नाग-कथाओं की समृद्ध परंपरा इस सांप-मानव संबंध को एक पवित्र आयाम देती हैं। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में यह आवश्यक हो गया है कि हम सांपों को केवल पौराणिक या रहस्यमयी दृष्टि से नहीं, बल्कि विवेक और तथ्य की दृष्टि से भी समझें। दुर्भाग्यवश, हिंदी फिल्मों, लोक कथाओं और टेलीविजन धारावाहिकों ने सांप को प्रतिशोध लेने वाले जीव के रूप में चित्रित किया है। कहा जाता है कि साँप अपनी मादा की हत्या का बदला लेते हैं, किसी की तस्वीर अपनी आँखों में कैद कर लेते हैं और वर्षों बाद भी शत्रु को पहचान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि साँप न तो इंसान को शिकार मानते हैं, न ही उन्हें कोई प्रतिशोध भाव होता है। वे केवल तभी काटते हैं जब उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता है। यानी, काटना उनका रक्षात्मक व्यवहार है, आक्रामक नहीं।

अब समय आ गया है कि हम सांपों के प्रति अपनी सोच में बदलाव लाएँ। देश में कई संस्थाएँ कार्यरत हैं जो सांपों की पहचान, संरक्षण और जन-जागरूकता के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। विद्यालयों में बच्चों को यह सिखाना बेहद आवश्यक है कि कौन से सांप विषैले होते हैं, उनके काटने पर क्या करना चाहिए, और किस प्रकार हमें उनसे डरने के बजाय समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। जब ज्ञान भय का स्थान लेगा, तभी सह-अस्तित्व की भावना उत्पन्न होगी। सांप न तो हमारे शत्रु हैं।

मतदाता सूची में सुधार पर सुप्रीम सहमति सराहनीय

–ललित गर्ग–

बिहार में मतदाता सूची सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी सिर्फ एक न्यायिक फैसला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल्य को पुष्ट करने वाला ऐतिहासिक एवं प्रासंगिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के लिए आधार, राशन और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर आम लोगों की मुश्किल हल करने की कोशिश की है। इससे प्रक्रिया आसान होगी और आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी। बेशक, फर्जी नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए लेकिन ऐसे अभियानों के दौरान आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से निकालने के बजाय, इस पर होना चाहिए कि एक भी नागरिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न रह जाए। विपक्ष को चाहिए कि वह इस फैसले को राजनीतिक हार न माने, बल्कि इसे अर्जित करने का, लोकतंत्र में आस्था बढ़ाने का और सबसे जरूरी, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखने का। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य केवल बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करना चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। चुनाव आयोग यदि चुनाव कराने को तैयार है, और इसकी जुड़ी किन्हीं प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि या खामी है तो उसका सुधार करना संविधान सम्मत है, तो फिर इस पर प्रश्नचिन्ह लगाने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रश्न जनता के मानस को उद्वेलित करता है, वह यह है कि विपक्ष बार-बार चुनावी प्रक्रियाओं, राष्ट्रीय हितों या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी एकमत होकर विरोध करता है, आखिर क्यों? बिहार में एसआईआर को लेकर जो याचिकाएं और बहसें सामने आईं, उनमें एक प्रमुख तर्क यह था कि समय उपयुक्त नहीं है, सरकार अस्थिर है, या सामाजिक समीकरण तैयार नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनता को प्रतिनिधित्व देने का अधिकार सर्वोपरि है। लेकिन त्रुटिपूर्ण या फर्जी मतदाता सूची से चुनाव कराना भी लोकतंत्र का अपमान है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि देर-सवेर नहीं, संवैधानिक कर्तव्य को समय पर निभाना जरूरी है।

अदालत ने एसआईआर पर कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन अपने इरादे की ओर इशारा तो कर ही दिया है। अदालत ने टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाया, वह उचित प्रतीत होता है। बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतनी विस्तृत कवायद के लिए शायद उतना वक्त न मिल पाए, जितना मिलना चाहिए।

बिहार में एसआईआर को लेकर जो असमंजस है, उसकी एक वजह निश्चित ही टाइमिंग है। जिनके पास जरूरी डॉक्युमेंट नहीं हैं, वे इतनी जल्दी उनका इंतजाम नहीं कर पाएंगे। हालांकि आयोग ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। वैसे बिहार में चुनाव को देखते हुए ही फर्जी मतदाताओं की संख्या बढ़ी या तथाकथित राजनीतिक दलों ने इन फर्जी मतदाताओं को बढ़ाया है। ऐसे में इन फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई अपेक्षित है। यह मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों की समीक्षा किस तरह होगी, यह बिहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। ऐसे में स्वाभाविक ही नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार इस प्रक्रिया का कैसा स्वरूप तय होता है?

भारतीय राजनीति में विपक्ष का कार्य सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना है, आलोचना करना है, लेकिन वह आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, राष्ट्र-विरोधी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाना हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर-एनआरसी जैसे कानून हों, अग्निपथ योजना हो, या राम मंदिर निर्माण-लगभग हर मुद्दे पर विपक्ष ने एकमत होकर विरोध किया है। चाहे चीन या पाकिस्तान से जुड़ी संवेदनशील मसले हों, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्णय, विपक्ष अक्सर उन बिंदुओं पर एक सुर में सरकार का विरोध करता है, जबकि ऐसे राष्ट्रीयता के मुद्दों पर विपक्ष को सरकार एवं देश के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। यह संयोग नहीं, एक दूषित राजनीतिक रणनीति बनती जा रही है कि जो सरकार करे, उसका विरोध करो, चाहे मुद्दा देशहित का ही क्यों न हो। इन स्थितियों में आम जनता का एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष देश के साथ है या सिर्फ सत्ता की भूख के साथ? क्या चुनाव प्रक्रिया पर विरोध करना लोकतंत्र का मजाक नहीं है? क्या न्यायपालिका के निर्णयों को चुनौती देना सिर्फ स्वार्थ की राजनीति नहीं? क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े होने से विपक्ष की राजनीति कमजोर हो जाएगी? जब विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है, तो उसका नैतिक बल कमजोर होता है, और जनता का विश्वास टूटता है। भारतीय राजनीति को अब रचनात्मक विपक्ष की जरूरत है, ऐसा विपक्ष जो सत्ता में नहीं है, फिर भी राष्ट्र के लिए सत्ता के साथ खड़ा हो सकता है। जो यह समझ सके कि लोकतंत्र सरकार और विपक्ष दोनों से चलता है, लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर है। बिहार में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति इस बात का प्रतीक है कि संस्थाएं अभी भी न्याय और संवैधानिकता की रक्षा कर रही हैं। लेकिन विपक्ष यदि इस निर्णय पर भी नकारात्मक रवैया अपनाता है, तो यह जनता की आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकासशील भारत की दिशा के विरुद्ध होगा। विपक्ष को चाहिए कि वह अपनी राजनीति को जनहित से जोड़े, जनविरोध से नहीं। विपक्ष यदि राष्ट्रहित में सोचने की दिशा में खुद को परिवर्तित नहीं करता, तो वह धीरे-धीरे प्रासंगिकता खो देगा।

भारतीय लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनावों पर टिकी होती है। इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया मतदाता सूची सुधार अभियान हाल ही में राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना।

पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के प्रमुख नेताओं को 10 वर्ष जेल की सजा

एजेंसी

लाहौर। पाकिस्तान के लाहौर और सरगोधा की दो अदालतों ने रात करीब साढ़े नौ बजे अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कई नेताओं को 10 वर्ष के जेल की सजा सुनाई। इन सभी के खिलाफ 09 मई, 2023 को इमरान की भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद देश में फैली हिंसा के आरोप में दर्ज मामलों पर यह फैसला आया है। डान अखबार की खबर के अनुसार, लाहौर आतंकवाद-रोधी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में रात करीब साढ़े नौ बजे शेरपाओ ब्रिज हिंसा मामले में फंसे पीटीआई नेताओं की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया। अदालत ने डॉ. यास्मीन राशिद, सीनेटर एजाज चौधरी, पूर्व गवर्नर उमर सरफराज चीमा और पूर्व प्रांतीय मंत्री मियां महमूदुर राशिद को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पीटीआई के चार वरिष्ठ नेताओं के अलावा जज ने अफजाल अजीम पहाट, अली हसन, खालिद कयूम और रियाज हुसैन समेत कई आरोपितों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, अदालत ने पीटीआई के उपाध्यक्ष और पूर्व विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। लाहौर में 09 मई को हुए दंगों से जुड़े किसी भी मामले में यह पहला फैसला है।

कूलिंग-ऑफ पीरियड प्रावधान को लेकर नेपाली कांग्रेस के महासचिव ने दी समर्थन वापसी की चेतावनी

काठमांडू। नेपाली कांग्रेस के महासचिव विश्व प्रकाश शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) सिविल सेवा विधेयक में कूलिंग-ऑफ पीरियड प्रावधान के संबंध में राज्य मामलों और सुशासन समिति की सिफारिश के खिलाफ जाती है तो वह सरकार को जारी समर्थन वापस ले सकती है। नेपाली कांग्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शर्मा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के अवकाश के तुरंत बाद राजनीतिक नियुक्ति के प्रावधान का नेपाली कांग्रेस कभी समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन लोगों ने कूलिंग-ऑफ अवधि के संबंध में गलत काम किया है, उन्हें दंडित किया जाएगा। इसे दो साल से बढ़ाकर ढाई साल किया जा सकता है, लेकिन इसे हटाया नहीं जाएगा। नेपाली कांग्रेस के महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री केपी ओली की पार्टी के कुछ सांसदों द्वारा नेशनल असेंबली के माध्यम से इसे बदलने केलिए जो संशोधन प्रस्ताव रखा है वह गठबंधन के फैसले के खिलाफ है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ओली को इस पर अपनी धारणा को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव शर्मा ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री के निर्देश पर इस कूलिंग पीरियड को हटाने का कोई प्रयास किया जाता है, या सरकार समिति की सिफारिश के खिलाफ काम करती है, तो कांग्रेस इस सरकार का समर्थन नहीं करती रहेगी।

पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी की सक्रिय राजनीति में वापसी पर प्रधानमंत्री ओली ने लगाया ब्रेक

काठमांडू। पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी के सक्रिय राजनीति में आने की घोषणा पर पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ब्रेक लगा दिया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) की केंद्रीय समिति की बैठक में भंडारी की पार्टी सदस्यता खारिज करने और सक्रिय राजनीति में कोई भूमिका नहीं देने का निर्णय किया गया है। सीपीएन-यूएमएल ने निष्कर्ष निकाला है कि पूर्व राष्ट्रपति भंडारी, जिन्होंने नेपाल सेना के राष्ट्राध्यक्ष और कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्य किया है, उन्हें पार्टी की राजनीति में वापस नहीं लौटना चाहिए। यूएमएल के प्रचार प्रमुख राजेंद्र गौतम के अनुसार, मंगलवार को आयोजित केंद्रीय समिति की बैठक के दौरान पार्टी ने निष्कर्ष निकाला कि एक पूर्व राष्ट्रपति को जो गणतंत्र का प्रतीक होता है उन्हें पार्टी का नेता या कैडर बनाना संविधान की भावना के खिलाफ होगा। मध्यरात तक चली पार्टी बैठक के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग में गौतम ने कहा कि पार्टी पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का सम्मान करती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस तरह का उच्च संवैधानिक पद संभाला है, उसे फिर से किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की भागीदारी राष्ट्रपति पद की गरिमा को कमजोर करेगी और जनता की आलोचना को आमंत्रित करेगी।

अमेरिका ज़रूरत पड़ने पर ईरान पर नए हमले करेगा : ट्रम्प

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर नए हमले कर सकता है। श्री ट्रम्प ने कल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिका के हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है और अगर जरुरत पड़ी तो अमेरिका फिर से ईरान पर हवाई हमले करेगा। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा था कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा । गौरतलब है कि गत 13 जून को, इज़रायल ने ईरान पर गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाने के बाद उसके ख़िलाफ़ सैन्य अभियान शुरू किया। ईरान पर हुए हवाई हमलों में परमाणु प्रतिष्ठानों, सैन्य नेतृत्व और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया और जिसमें उसके कई सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई।

एपस्टीन विवाद के बीच ट्रंप ने ओबामा पर लगाया देश से 'विश्वासघात' का आरोप

एजेंसी

वॉशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर देश से 'विश्वासघात' का आरोप लगाया, जिसके बाद ओबामा के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया सामने आई। प्रवक्ता ने इन आरोपों को 'बेतुका' और ध्यान भटकाने की एक कमजोर कोशिश बताया। समाचार एजेंसी के मुताबिक, जब मीडिया ने ट्रंप से दिवंगत अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन से जुड़े मामले पर सवाल किया, तो उन्होंने ओबामा को टारगेट करना शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की और पकड़े गए। इसके लिए सख्त सजा होनी चाहिए। यह देश से विश्वासघात था। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को गिरोह का मुखिया बताते हुए आरोप लगाया कि

डेमोक्रेट्स ने 2016 से लेकर 2020 तक चुनावों में कथित तौर पर हेराफेरी की। इस पार्टी में जो बाइडेन और हिलेरी क्लिंटन भी शामिल हैं। अभी तक डेमोक्रेट्स की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ओबामा के प्रवक्ता ने पहले ही ट्रंप के आरोपों को बेतुका और ध्यान भटकाने का प्रयास बताया है।पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रवक्ता पैट्रिक रोडनबश ने कहा, राष्ट्रपति पद के सम्मान में, हमारा कार्यालय आमतौर पर व्हाइट हाउस से निरंतर आने वाले झूठ और गलत जानकारी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन यह दावे इतने अपमानजनक हैं कि इन पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। यह अजीबो-गरीब आरोप पूरी तरह से बेतुके हैं। यह ध्यान भटकाने की एक कमजोर कोशिश है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राजनीतिक और व्यावसायिक दिग्गजों से व्यापक संबंध रखने वाले जेफरी एपस्टीन पर यौन अपराधों के आरोप लगे थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2019 में जेल में उनकी मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या करार दिया गया। एपस्टीन के अमेरिका की राजनीतिक और कारोबारी हस्तियों से गहरे संबंध थे। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि अगर वह दोबारा चुने जाते हैं।

श्रीलंका की सरकारी एयरलाइंस में हुए भ्रष्टाचार की जांच नए सिरे से कराने का फैसला

एजेंसी

कोलंबो। श्रीलंका की सरकारी 'एयरलाइंस लिमिटेड और एयरपोर्ट एंड एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' में हुए भ्रष्टाचार की परतें जल्द खुल सकती हैं। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने नए सिरे जांच कराने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जांच से दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। जांच के दायरे में 2010 से 2025 के बीच हुए सौदों को भी शामिल किया गया है। डेली मिरर अखबार की खबर के अनुसार, श्रीलंका की सरकार ने सरकारी एयरलाइंस में हुई धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोपों की जांच के लिए विशेष राष्ट्रपति जांच समिति गठित की है। इस समिति ने बीते कल राष्ट्रपति सचिवालय में बैठक के दौरान दिसानायके से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि लंबे समय से चल रहे कुप्रबंधन और उचित जांच के अभाव ने दोनों संस्थानों ने विश्वसनीयता खो दी है। प्रभावी अंकुश न होने के कारण बेधड़क गोलमाल होता रहा। उन्होंने समिति से कहा कि तत्काल जांच करकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस रिपोर्ट में कदाचार रोकने के उपाय भी शामिल किए जाएं। इस समिति में राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव केएनएम कुमारसिंघे को सचिव और संयोजक नियुक्त किया गया है। समिति के सदस्यों में सेवानिवृत्त महालेखा परीक्षक एचएम गामिनी विजेसिंघे, सेवानिवृत्त अतिरिक्त महानिदेशक सीमा शुल्क ज्ञानसिरी सेनानायके, राष्ट्रीय बचत बैंक के अध्यक्ष दुशांत बसनायके, अटॉर्नी-एट-लॉ, डॉन चामिंडा जे. अथुकोराला और सार्वजनिक उद्यम विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक एनएएचके विजेरत्ने हैं। जांच के दायरे में श्रीलंकाई एयरलाइंस और हवाई अड्डे एवं विमानन सेवाओं को शामिल किया गया है।

अमेरिका से जापान ने की ट्रेड डील, देना होगा 15 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ

एजेंसी

वाशिंगटन । दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और जापान के बीच ट्रेड डील हो गई है। इस डील के तहत अमेरिका, जापानी प्रोडक्ट्स पर 15 प्रतिशत का रेसिप्रोकल ट्रैरिफ लगाएगा।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड डील के तहत उनके प्रशासन ने जापानी उत्पादों पर 15 प्रतिशत का रेसिप्रोकल ट्रैरिफ लगाने का फैसला किया है, जो कि पहले लगाए गए टैरिफ से 10 प्रतिशत कम है।ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह घोषणा ऐसे समय में की है, जब दक्षिण कोरिया और अन्य देश अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे अधिक रेसिप्रोकल ट्रैरिफ से बचा जा सके या उन्हें कम किया जा सके। अमेरिकी प्रशासन द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तारीख 1 अगस्त निर्धारित की गई है। अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जापान अपने देश को कारों और ट्रकों, चावल और कृषि उत्पादों एवं अन्य चीजों सहित व्यापार

के लिए खोल देगा। हालांकि, जापान, अमेरिका को 15 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ देगा। इस महीने की शुरुआत में जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा को लिखे एक पत्र में, ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका जापान पर 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, जो ट्रंप द्वारा शुरू में घोषित टैरिफ से एक प्रतिशत अधिक है। ट्रंप ने जापान के साथ हुए इस समझौते को शायद अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया और कहा कि एशियाई देश ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है, जिसका 90 प्रतिशत लाभ उसे मिलेगा। उन्होंने निवेश योजना के बारे में विस्तार से नहीं बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, इस समझौते से लाखों नौकरियां पैदा होंगी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले, ट्रंप ने फिलीपींस के साथ भी एक समझौते की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देश 19 प्रतिशत टैरिफ का भुगतान करेगा।

गाजा युद्ध में पूरी जीत जरूरी : इजरायली रक्षा मंत्री

एजेंसी

यरूशलम । इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा है कि गाजा में चल रहे युद्ध में पूरी तरह से जीत हासिल करना जरूरी है। मंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, काट्ज ने इजरायली सेना प्रमुख इयाल ज़मीर और अन्य वरिष्ठ कमांडरों के साथ हालात की समीक्षा के दौरान यह बात कही। काट्ज ने कहा, हम युद्ध के लक्ष्यों को पाने के सबसे क़रीब हैं। अभी दो जगह बची हैं - गाजा और यमन। हमें दोनों मोर्चों पर पूरी जीत के लिए काम करना होगा। समाचार एजेंसी के अनुसार, यह बयान ऐसे समय आया है जब कतर की राजधानी दोहा में गाज़ा युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है और इजरायली मीडिया में कुछ प्रगति की खबरें भी आई हैं। बयान के अनुसार, काट्ज़ ने युद्ध के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के महत्व पर ज़ोर दिया, जिसमें मुख्यतः सभी इजराइल बंधकों की

वापसी और हमास का आत्मसमर्पण शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। उन्होंने पिछले महीने के छोटे युद्ध में मिली उपलब्धियों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने की बात कही कि ईरान अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम दोबारा शुरू न कर पाए।काट्ज़ ने यह भी कहा कि सीरिया और लेबनान सहित विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण बिंदुओं और सुरक्षा क्षेत्रों में इजरायली सेना की उपस्थिति इजरायल समुदायों की रक्षा के लिए एक सुरक्षा आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि इजरायली सेना पश्चिमी तट के शरणार्थी शिविरों में रहेगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त शिविरों में भी काम करेगी।

पार्टी की ओर से बढ़ते दबाव के बीच जापानी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने के संकेत दिए

एजेंसी

टोक्यो । जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने अपने करीबियों को बताया है कि वह अगस्त तक अपने पद से हट सकते हैं। उन्होंने हाल ही में हुए हाउस ऑफ काउंसिलर्स के चुनाव में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की करारी हार की आंतरिक समीक्षा के बाद यह इच्छा जताई है। यह जानकारी मैनिची अखबार ने दी। समाचार एजेंसी के अनुसार, इशिबा बुधवार को अपने राजनीतिक भविष्य पर चर्चा के लिए एलडीपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि, शुरू में इशिबा ने चुनावी झटके के बावजूद पद पर बने रहने का ऐलान किया था, लेकिन पार्टी के भीतर उनके इस्तीफे की मांग अब तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पद

छोड़ने की सटीक तारीख अभी तय नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि अमेरिका और जापान के बीच एक ट्रेड डील हुई है, जिसमें अमेरिका में जापान से आने वाले इंपोर्ट पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। जब प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा से इस व्यापार समझौते के उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रभाव को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, मैं तब तक कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, जब तक समझौते की विषय-वस्तु की पूरी तरह से जांच नहीं कर लेता। इशिबा को उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के भीतर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने ऊपरी सदन (हाउस ऑफ काउंसिलर्स) के चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन की करारी हार के बावजूद सरकार में बने रहने का वादा किया था। यह चुनाव उस वक्त हुआ, जब जापान में बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं। इसके साथ ही टैरिफ को लेकर भी लोग चिंतित हैं। एक प्रेस वार्ता में इशिबा ने कहा था, मैं पद पर बना रहूंगा और इन चुनौतियों को सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। उम्मीद है कि जापानी प्रधानमंत्री बुधवार को चुनाव परिणामों पर चर्चा करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेताओं से मिलेंगे।

बांग्लादेश में ट्रक और बस में टक्कर, छह लोगों की मौत

एजेंसी

ढाका। बांग्लादेश के राजशाही विभाग के ग्राणीण क्षेत्र में आज सुबह हुए सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। फिलहाल एक मृतक की पहचान हो सकी है। कुछ लोग घायल हैं। उन्हें पुलिस ने पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर में बोनपारा हाइवे पुलिस थाना प्रभारी इस्माइल हुसैन के हवाले से बताया गया है कि सुबह लगभग 9:30 राजशाही विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के नाटोर जिला के बरईग्राम उपजिला में ट्रक और मिनी बस के बीच हुई टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना बोनपारा-हतीकुमरुल राजमार्ग पर एयरमारी में तारमुज पंप क्षेत्र के सामने हुई। मृतकों में अभी तक केवल बस चालक 32 वर्षीय रुबेल हुसैन की पहचान हो पाई है। वह मेहरपुर के गंगनी उपजिला का रहने वाला है।हाइवे थाना प्रभारी हुसैन ने कहा कि इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग बस यात्री हैं। यह बस मेहरपुर से ढाका जा रही थी। एयरमारी में विपरीत दिशा से आ रहे सीमेंट से लदे ट्रक से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। चालक रुबेल हुसैन समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें बरईग्राम उपजिला स्वास्थ्य परिसर ले जाया गया। वहां एक घायल ने दम तोड़ दिया। शेष घायल यात्रियों को बाद में राजशाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी मिजानुर रहमान के अनुसार, बस एक अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी तभी उसकी टक्कर सामने से आ रहे ट्रक से हो गई। मारे गए छह लोगों में चार महिलाएं और दो पुरुष हैं। हाइवे पुलिस के अनुसार, ट्रक को जब्त कर लिया गया है, लेकिन चालक घटनास्थल से भागने में सफल रहा।

अमेरिका ने यूनेस्को से अपनी वापसी की घोषणा की

एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र । अमेरिका ने यूनेस्को से अपनी वापसी की घोषणा कर दी है। विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यूनेस्को विभाजनकारी सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को बढ़ावा दे रहा है और सतत विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में यह दूसरी बार है जब अमेरिका पेरिस स्थित यूनेस्को से अलग हो रहा है। वाशिंगटन दो साल पहले अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन के कार्यकाल में इसमें फिर से शामिल हुआ था।नोटिस जारी करने के बाद, ब्रूस ने कहा कि यह वापसी अगले साल के अंत में प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए वैश्विक, वैचारिक एजेंडा हमारी अमेरिका प्रथम विदेश नीति के विपरीत है और यूनेस्को में निरंतर भागीदारी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हित में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र

महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा,'यूनेस्को की स्थापना के बाद से अमेरिका ने इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई है, उसे देखते हुए, उन्हें इस वापसी पर गहरा खेद है। ट्रंप प्रशासन के लिए प्रमुख मुद्दे यूनेस्को की इजरायल विरोधी नीतियों को लेकर हैं, जिनका वह इजराइल के साथ विरोध करता है, और फिलिस्तीन की सदस्यता है। ब्रूस ने कहा, 'फिलिस्तीन राज्य' को सदस्य राज्य के रूप में स्वीकार करने का यूनेस्को का निर्णय अत्यधिक समस्याग्रस्त है। यह अमेरिकी नीति के विपरीत है, और इसने संगठन के भीतर इजरायल विरोधी बयानबाजी को बढ़ावा दिया है।अमेरिका का यूनेस्को से बाहर होना, ट्रंप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तीखी आलोचना और उनसे खुद को अलग करने के अनुरूप है।

कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को अलग कर लिया, कोविड महामारी से निपटने के उसके तरीके की आलोचना की और उस पर अपनी भूमिका का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा की महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने कहा कि अमेरिका का यह निर्णय बहुपक्षवाद के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है, और सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे कई साझेदारों को प्रभावित कर सकता है - वे समुदाय जो विश्व धरोहर सूची में स्थान पाने, रचनात्मक शहर का दर्जा पाने और विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनने की इच्छा रखते हैं।

उन्होंने कहा, हालांकि यह खेदजनक है, लेकिन इस घोषणा की उम्मीद थी, और यूनेस्को ने इसके लिए तैयारी कर ली है। 2023 में यूनेस्को को अमेरिका का योगदान 28 मिलियन डॉलर था, जो संगठन के बजट का 22 प्रतिशत था अजोले ने कहा, आज, बड़ी संख्या में सदस्य देशों और निजी योगदानकर्ताओं के निरंतर समर्थन से संगठन वित्तीय दृष्टि से बेहतर संरक्षित है, जिससे अमेरिकी योगदान घटकर 8 प्रतिशत रह गया है।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने किया 'भारत-पाक तनाव' कम कराने का दावा, भारत ने कहा- आपसी बातचीत से सुलझा मुद्दा

एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र । अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को दोहराया है कि उन्होंने मई में भारत-पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाया था, लेकिन भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि यह मामला द्विपक्षीय रूप से हल किया गया। कार्यवाहक अमेरिकी प्रतिनिधि डोरोथी शीया ने कहा कि पिछले तीन महीनों में अमेरिकी नेतृत्व की भूमिका में जिन तनावपूर्ण संघर्षों को कम किया गया, उनमें भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव भी शामिल है। यह तनाव पहलगाम में 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' की ओर से आतंकवादी हमले के बाद पैदा हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप को उस दावे को दोहराया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति अक्सर करते आए हैं। डोरोथी ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोनों पक्षों को इन प्रस्तावों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी हम सराहना और समर्थन करते हैं।

दूसरी ओर, भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने दृढ़ता से कहा कि यह पाकिस्तान के भारत से अनुरोध पर सीधे तौर पर संपन्न हुआ था।उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने जब अपने प्राथमिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, तो पाकिस्तान के अनुरोध पर सैन्य गतिविधियों को सीधे तौर पर रोक कर दिया गया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक केंद्रित, नपी-तुली और गैर-उत्तेजक कार्रवाई थी। हरीश ने बताया कि यह अभियान सुरक्षा परिषद के उस बयान से प्रेरित था, जिसमें पहलगाम हमले के अपराधियों, योजनाकारों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत पर जोर दिया गया।

इस अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में स्थित आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया। डोरोथी और पी. हरीश, सुरक्षा परिषद में बहुपक्षवाद और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान विषय पर खुले विमर्श के दौरान बोल रहे थे, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इसहाक डार ने की। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष रुकवाया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी उनके इस दावे का समर्थन किया है।

पाकिस्तान में मानसून का कहर, नदी-नाले उफान पर, भूस्खलन, रास्ते बंद, 234 लोगों की मौत

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान मानसून से त्राहिमाम-त्राहिमाम है। बरसात, बाढ़ और भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए हैं। बादलों के फटने से बड़ी तबाही हुई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के ताजा आंकड़े हृदयविदारक हैं। इन आंकड़ों में 26 जून से अब तक कम से कम 234 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि 596 लोग घायल हुए हैं और 826 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राहत, बचाव और खोज अभियान में सेना को शामिल किया गया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर में एनडीएमए के ताजा आंकड़े साझा किए गए हैं। कहा गया है कि अब तक 203 पशुओं की मौत हो चुकी है। बड़े पैमाने पर परिवार विस्थापित हुए हैं। मुल्क में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ। राहत, बचाव और खोज अभियान के तहत 450 लोगों को बचाया गया है। प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 27 राहत और चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि खतरा अभी टला नहीं है। उत्तरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। गिलगित-बाल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में स्थिति गंभीर है। डायमर के उपायुक्त अत्ता-उर-रहमान के अनुसार, सोमवार को बादल फटने से बाबूसर में चार पर्यटकों और एक स्थानीय निवासी सहित कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई।

ढाका विमान हादसा :बांग्लादेश सरकार ने सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर की कार्रवाई, भड़की अवामी लीग

एजेंसी

ढाका । बांग्लादेश में हाल ही में हुए विमान हादसे के बाद प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिस पर मुहम्मद युनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कार्रवाई की। हालांकि, अब अवामी लीग ने सरकार की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस की कार्रवाई में कम से कम 75 छात्र घायल हुए, जिनका ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज किया गया। हादसे की जगह और बांग्लादेश की राजधानी में सचिवालय भवन के बाहर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुए, जिसमें छात्रों ने अंतरिम सरकार के शिक्षा सलाहकार और शिक्षा सचिव के तत्काल इस्तीफे की मांग की। इस विमान हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर बच्चे बताए जा रहे हैं, और 165 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

अंतरिम सरकार के कानून और शिक्षा सलाहकारों के साथ-साथ युनुस के प्रेस सचिव को छात्रों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। वे इस हादसे के बाद निरीक्षण के लिए संस्थान का निरीक्षण करने के लिए गए थे। छात्रों ने उनके इस्तीफे की मांग की और कहा कि सरकार ने हादसे से संबंधित गलत जानकारी दी है।अवामी लीग ने जारी एक बयान में कहा, माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज में फाइटर जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और कर्मचारियों पर व्यवस्थित रूप से अत्याचार, धोखा और दमन किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में हताहतों की संख्या छिपाने से लेकर कानून प्रवर्तन बलों को तैनात करने, साउंड ग्रेनेड, आंसू गैस और असली गोलियों का इस्तेमाल करने तक, इस शासन ने राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्र के कल्याण में पूरी तरह विफलता दिखाई है।बयान में आगे कहा गया, हताहतों की सूची को पारदर्शी रखने के बजाय, शासन ने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए कानून प्रवर्तन बलों को उतारा, ताकि राष्ट्र को अंधेरे में रखा जाए। हताहतों की सूची बताने की बार-बार की मांग के बावजूद, दुखी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों पर पुलिस ने हमला किया, मानवाधिकारों की पूरी तरह अनदेखी की, जिससे परिवारों और साथी छात्रों को और भी अधिक आघात पहुंचा है। पार्टी ने दावा किया कि सलाहकारों को हटाने की मांग के साथ सड़कों पर लाखों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि युनुस शासन अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। अवामी लीग ने कहा, जनता का गुस्सा तब साफ दिखाई दिया, जब यूनुस शासन के दो सलाहकारों और प्रेस सचिव को दुर्घटनास्थल के दौरे के दौरान स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने मृतकों की संख्या के बारे में गवाहों के बयानों को गलत सूचना बताकर खारिज कर दिया।अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए पार्टी ने जोर देकर कहा कि माइलस्टोन कॉलेज सहित कई जगहों पर छात्रों और शिक्षकों पर कानून प्रवर्तन बलों की तैनाती और साउंड ग्रेनेड, असली गोलियों और घातक हथियारों का इस्तेमाल न केवल शासन की मानवाधिकारों को बनाए रखने की जिम्मेदारी को कमजोर करता है, बल्कि राष्ट्रीय संकट के चरम पर भी उसकी ताकत पर निर्भरता को उजागर करता है। पार्टी ने कहा, हम इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसने देशव्यापी प्रदर्शन भड़का दिए। मरीजों को अस्पतालों में प्रवेश करने से रोका गया, जबकि राजनीतिक दलों के नेताओं और सलाहकारों को अस्पताल में जाने और पीड़ितों के साथ फोटो खिंचवाने की अनुमति दी गई, जो चिकित्सा सेवाओं को बाधित करके राजनीतिक अंक हासिल करने का एक बर्बर प्रदर्शन है। बांग्लादेश में अराजकता को उजागर करते हुए अवामी लीग ने आगे कहा, विमान हादसे के पीड़ितों के लिए रक्तदान करने आए स्वयंसेवकों पर पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया।

मामूली कमजोरी के साथ बंद हुआ बाजार, निवेशकों को 1.39 लाख करोड़ का नुकसान

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार आज दबाव में कारोबार करने के बाद मामूली कमजोरी के साथ सपाट स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी। बाजार खुलते ही खरीदारी के सपोर्ट से निफ्टी और सेंसेक्स की चाल में थोड़ी और तेजी आई, लेकिन इसके बाद बिकवाली का दबाव बन जाने की वजह से इन दोनों सूचकांकों ने लाल निशान में गोता लगा दिया। शेयर बाजार की चाल में आज पूरे दिन लगातार उतार-चढ़ाव होता रहा। दिनभर का कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.02 प्रतिशत और निफ्टी 0.12 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुए। आज दिनभर के कारोबार के दौरान सभी सेक्टोरल इंडेक्स कमजोरी के साथ बंद हुए। पीएसयू बैंक, फार्मास्युटिकल और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में आज जमकर बिकवाली होती रही। इसी तरह आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस और टेक इंडेक्स भी कमजोरी के साथ बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में भी आज लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.62 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में आई कमजोरी के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में सवा लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी हो गई।

अकासा एयर के बेड़े में 2032 तक होंगे 226 विमानः अंकुर गोयल

नई दिल्ली। भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन अकासा एयर ने 2032 तक अपने विमानों के बेड़े की संख्या को 30 से बढ़ा कर 226 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अकासा एयर ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष 2024-25 में 49 फीसदी राजस्व वृद्धि और 50 फीसदी मार्जिन सुधार दर्ज किया है। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अंकुर गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अकासा एयर ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 49 फीसदी राजस्व वृद्धि और 50 फीसदी मार्जिन सुधार दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि एयरलाइन की योजना इस अवधि के दौरान सालाना 25 से 30 फीसदी क्षमता जोड़ने की है। अंकुर गोयल ने बताया कि बढ़ती लाभप्रदता, 27 विमानों और 1.6 करोड़ से अधिक यात्रियों की सेवा के साथ एयरलाइन ने दीर्घकालिक विकास और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। उन्होंने कहा कि अकासा एयर ने इस साल 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के लिए मजबूत राजस्व वृद्धि दर्ज की है।

शांति गोल्ड का आईपीओ 25 जुलाई को खुलेगा, प्राइस बैंड 189-199 रुपये प्रति शेयर

नई दिल्ली। स्वर्ण आभूषण विनिर्माता कंपनी शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) निवेशकों के लिए शुक्रवार, 25 जुलाई को खुलेगा और 29 जुलाई को बंद होगा। कंपनी ने इसके लिए मूल्य दायरा (प्राइस बैंड) 189-199 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इसके शेयर 1 अगस्त को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने की संभावना है। कंपनी ने जारी बयान में बताया कि 10 रुपये अंकित मूल्य वाले आईपीओ के लिए मूल्य का दायरा 189-199 रुपये प्रति शेयर तय है। ये आईपीओ पूरी तरह 1.81 करोड़ इक्विटी शेयरों तक के नए शेयरों का निर्गम है, जिसमें बिक्री की पेशकश (ओएफएस) का कोई घटक शामिल नहीं है। निवेशक न्यूनतम 75 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 75 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं। कंपनी इस इश्यू से 360 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड इस निर्गम से प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल जयपुर में इकाई स्थापित करने, कंपनी की कार्यशील पूंजी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने, कर्ज भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए करेगी। चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र बुक-रनिंग लीड मैनेजर है और बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू का रजिस्ट्रार है।

सिप्ला हेल्थ ने एस्टाबेरी के नये कैंपेन 'गेट द रिच लुक' की घोषणा की

नई दिल्ली। वेलनेस कैटेगरी की अग्रणी कंपनी सिप्ला हेल्थ ने अपने ब्यूटी और पर्सनल केयर ब्रांड एस्टाबेरी के नवीनतम कैंपेन 'गेट द रिच लुक' की घोषणा की है। 'रिच लुक' का मतलब है ऐसी मुलायम और स्वस्थ त्वचा जो बिना किसी मेकअप या फिल्टर के स्वाभाविक रूप से दमकती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आत्मविश्वास को निखारती है। कंपनी ने बताया कि प्रकृति से प्रेरित और देश की महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया यह कैंपेन, स्वाभाविक रूप से दमकती, सेहतमंद त्वचा का उत्सव है जो महिलाओं को जीवन के हर मोड़ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की ताकत देता है। उपभोक्ताओं द्वारा साझा की गई असली कहानियों से प्रेरणा लेते हुए, इस फिल्म में दिखाया गया है कि एस्टाबेरी के सरल और प्रभावशाली स्किनकेयर समाधान महिलाओं को स्वाभाविक रूप से दमकता हुआ 'रिच लुक' हासिल करने में कैसे मदद कर सकते हैं। यह फिल्म हल्के-फुल्के और मनोरंजक अंदाज़ में जीवन के उन परिचित पलों को आकर्षक ढंग से दर्शाती है, जहां एक मामूली से ब्यूटी अपग्रेड से कोई महिला अपना लुक बेहतर बना सकती है, चाहे वह किसी नए व्यक्ति से मिलना हो।

दुबई-स्पेन यात्रा में मप्र मिले 11,119 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 14 हजार रोजगार सृजन की संभावना

एजेंसी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 13 से 19 जुलाई तक दुबई-स्पेन की सफल निवेश यात्रा से प्रदेश को वैश्विक निवेश के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान मिली है और यूरोप तथा खाड़ी देशों में यह संदेश पहुंचा है कि मध्य प्रदेश निवेश मित्र राज्य है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में कुल 11,119 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे लगभग 14 हजार से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है। मुख्यमंत्री मंत्रालय में मंत्री-परिषद की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित कर रहे थे। दुबई-स्पेन की सफल निवेश यात्रा के लिए मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पुष्प गुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर उनका अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेन में उद्यानिकी, फल उत्पादन और कृषि क्षेत्र का प्रबंधन सराहनीय और अनुकरणीय है। इस क्षेत्र में

आधुनिकतम तकनीक अपनाने के लिए प्रदेश के कृषक दलों को स्पेन भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि वस्त्र व्यवसाय में लगे अंतरराष्ट्रीय समूह, हरित ऊर्जा के उपयोग और प्राकृतिक खेती से उत्पादित सामग्री को विशेष महत्व देते हैं। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय बाजार में विशेष महत्व है। राज्य सरकार प्रदेश के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने की पहल करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुबई, मैड्रिड, बार्सिलोना में आयोजित इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश'' कार्यक्रम एवंप्रवासी भारतीयों से चर्चा'' में 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। मध्यप्रदेश में टेक्समास (दुबई) के साथ एमओयू हुआ है। अरब देशों के निवेशकों को आकर्षित करने के लिये अरब चैम्बर ऑफ कामर्स के साथ भी एमओयू किया गया। इसी तरह निवेश, तकनीकी सहयोग और सतत ?डिजिटल अधोसंरचना विकास के लिये सबमर टेक्नॉलाजीस एसएल के साथ एमओयू किया गया। दुबई में इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्टील मेन्युफेक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, डिफेंस, वेयरहाउसिंग और सस्टेनेबल सिटी जैसे क्षेत्रों में कम्पनियों से कुल 6801 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। स्पेन में डिजिटल, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन में कम्पनियों से 4318 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें उन्नत बायोफ्यूल और एसएएफ प्रोजेक्ट्स में 4000 करोड़ का एक बड़ा निवेश प्रस्ताव भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि संपूर्ण वैश्विक जगत में विख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैन की धरती पर भूतभावन महाकाल बाबा विराजमान हैं।

जिंदल स्टील एंड पावर का नाम बदलकर कर दिया गया जिंदल स्टील

एजेंसी

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र की कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर (जेएसपीएल) का नाम बदलकर जिंदल स्टील लिमिटेड कर दिया गया है। कंपनी ने भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी के नाम में यह बदलाव किया है। ये नाम 22 जुलाई 2025 से प्रभावी हो गया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में बताया कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जिंदल स्टील एंड पावर (जेएसपीएल) का नाम बदलकर अब जिंदल स्टील लिमिटेड कर दिया गया है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के कंपनी रजिस्ट्रार से अनुमोदन मिलने के बाद

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर जिंदल स्टील लिमिटेड कर दिया है, जो 22 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। जिंदल स्टील ने कहा कि कंपनी अपने नए नाम के तहत शेयरों द्वारा सीमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में काम करना जारी रखेगी। कंपनी ने जारी बयान में कहा कि इस्पात निर्माण में अपनी मुख्य ताकत पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि अब हम जिंदल स्टील हैं। कंपनी ने कहा कि ये परिवर्तन कंपनी के इस्पात क्षेत्र के अपने मुख्य व्यवसाय पर केंद्रित ध्यान और एक समर्पित, भविष्योन्मुखी इस्पात उद्यम के रूप में उसकी रणनीतिक दिशा को दर्शाता है। नया नाम भारत और विश्व स्तर पर पहचान की स्पष्टता को पुष्ट करता है।

आईआरएफसी ने रचा इतिहास:अब तक का सबसे मजबूत तिमाही प्रदर्शन, शुद्ध लाभ में 10.71 प्रतिशत की उछाल

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे की वित्तीय शाखा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया। कंपनी का शुद्ध लाभ 10.71फीसदी की वृद्धि के साथ 1,745.69 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 1,576.83 करोड़ था। यह आईआरएफसी के इतिहास में किसी एक तिमाही में सबसे अधिक शुद्ध लाभ है कंपनी ने इस तिमाही में कुल 6,918.24 करोड़ की आय दर्ज की, जो पिछले वर्ष की 6,766.03 करोड़ से अधिक है। इंटरस्ट मार्जिन भी 1.53त्न की दर से बेहतर हुआ है। इस दौरान कंपनी की कुल परिसंपत्तियां बढ़कर ?4,41,650 करोड़ तक पहुंच गईं, जो पिछले वर्ष ?4,24,230 करोड़ थीं। आईआरएफसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मनोज़ कुमार दुबे ने इस प्रदर्शन को रणनीतिक वित्तीय प्रबंधन और परिचालन दक्षता का परिणाम बताया। उन्होंने कहा, हम

INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATIO

रेलवे इकोसिस्टम में एक मजबूत वित्तीय स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। न्यूनतम ओवरहेड, उत्कृष्ट रेटिंग प्रोफाइल और विविध पोर्टफोलियो के साथ हमने ऐतिहासिक स्तर तक प्रदर्शन किया है। शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा। उसका बाजार पूंजीकरण अब ?2,54,423.96 करोड़ के स्तर तक पहुंच चुका है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में भी सुधार देखा गया है, जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है। इस तिमाही में ई-डेट, ई-ट्रैक्टिव और रेलवे से जुड़े अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से पूंजी जुटाने के प्रयासों में भी तेजी देखी गई है। कंपनी ने 7.44 प्रतिशत की दर से उच्च प्रतिफल वाले निवेश साधनों के जरिए अपना राजस्व बढ़ाया है। गौरतलब है कि हाल ही में सरकार द्वारा आईआरएफसी को 'नवरत्न' का दर्जा प्रदान किया गया था, जिससे कंपनी को निवेश और संचालन में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इसका सकारात्मक प्रभाव इस तिमाही के प्रदर्शन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आईआरएफसी द्वारा जारी आंकड़े संकेत देते हैं कि कंपनी न केवल रेलवे के वित्तपोषण में अपनी भूमिका को और व्यापक बना रही है, बल्कि राष्ट्रीय अवसंरचना विकास में भी एक निर्णायक भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

केंद्र ने 22 राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए जारी किए 9578.40 करोड़ रुपये : गृह मंत्रालय

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 22 राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के तहत 9578.40 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह जानकारी लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी गृह राज्य मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि यह वित्तीय सहायता प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत के तौर पर दी जाती है, न कि पीड़ितों द्वारा दावे के आधार पर हुए नुकसान की भरपाई के रूप में। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने बताया कि भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून इस वर्ष सामान्य तिथि 1 जून से आठ दिन पहले 24 मई को केरल में पहुंच गया। यह पिछले 17 वर्षों में मानसून का सबसे जल्दी आगमन है। मुंबई में मानसून 26 मई को पहुंचा, जबकि सामान्य तिथि 11 जून होती है- यह पिछले 75 वर्षों में सबसे पहले पहुंचने वाला मानसून है।

देश भर में मानसून 29 जून को ही पहुंच गया, जो सामान्य तिथि 8 जुलाई से 9 दिन पहले है। जून के दूसरे पखवाड़े और जुलाई के पहले 15 दिनों में बारिश की तीव्रता सबसे अधिक रही। खासकर गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की गंभीर घटनाओं को देखते हुए, केंद्र सरकार ने बिना राज्य ज्ञापन की प्रतीक्षा किए, एक अंतर-मंत्रालयीय केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया है। यह टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर क्षति का आकलन करेगी। नित्यानंद राय ने कहा कि एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के तहत दी जाने वाली राशि राहत कार्यों के लिए होती है, न कि व्यक्तिगत क्षति के मुआवज़े के रूप में। राज्य सरकारों को पहले से जारी एसडीआरएफ की राशि से अपने स्तर पर राहत कार्य संचालित करने होते हैं। जुलाई 15, 2025 तक जारी 9578.40 करोड़ रुपये की राशि से राज्यों को राहत कार्यों में मदद मिलेगी। संबंधित राज्यों को आवंटित और जारी राशि की विस्तृत जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

स्टॉक मार्केट में मोनिका एल्कोबेव की सपाट एंट्री, मामूली फायदे में आईपीओ निवेशक

एजेंसी

नई दिल्ली। एल्कोहलिक बेवरेजेज का आयात करके भारत और पड़ोसी देशों में बिक्री करने वाली कंपनी मोनिका एल्कोबेव के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मामूली बढ़त के साथ एंट्री की। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 286 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 0.70 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 288 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण शेयरों में तेजी का रुख बना। सुबह 10-30 बजे तक के कारोबार के बाद कंपनी के शेयर 289.50 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इससे अभी तक के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को करीब 1.22 प्रतिशत का मुनाफा हुआ है। मोनिका एल्कोबेव का 165.63 करोड़ रुपये का आईपीओ 16 से 18 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से

एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 4.08 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 2.54 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 8.86 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 2.29 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 137.02 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिए बेचे गए हैं। नए शेयरों के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने पुराने कर्जों को चुकाने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 13.03 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 16.60 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 23.11 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 30 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 238.36 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए 4 साल में 9.11 फीसदी से घटकर 2.58 फीसदी हुआ : वित्त राज्य मंत्री

एजेंसी

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) में लगातार गिरावट आई है। मार्च 2021 से मार्च 2025 तक पीएसबी का एनपीए 9.11 फीसदी से घटकर 2.58 फीसदी हो गया है। इसके साथ ही खुदरा महंगाई दर भी जून में घटकर 2.1 फीसदी पर आ गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। पंकज चौधरी ने कहा, सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) दोनों ने बढ़ते एनपीए की समस्या से निपटने और वसूली की दरों में सुधार के लिए कई उपाय पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके कारण पिछले पांच वित्त वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल एनपीए मार्च 2021 के 9.11 फीसदी से घटकर मार्च 2025 तक 2.58 फीसदी हो गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार और आरबीआई ने महंगाई को नियंत्रित करने और आम नागरिकों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रमुख मौद्रिक और राजकोषीय उपाय किए हैं। मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच रेपो रेट में 2.50 आधार अंकों (4 फीसदी से 6.5 फीसदी) की वृद्धि की और उसके बाद जनवरी 2025 तक इसे 6.5 फीसदी पर बनाए रखा। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 के 5.4 फीसदी से गिरकर वित्त वर्ष 2024-25 में 4.6 फीसदी हो गई।

सर्राफा बाजार में जोरदार तेजी, सोना और चांदी की बढ़ी चमक

++++++++++++++++++

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज जोरदार तेजी का रुख नजर आ रहा है। सोना आज 1,050 रुपये से लेकर 1,140 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज 2,200 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई है। कीमत में उछाल आने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,01,300 रुपये से लेकर 1,01,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 92,860 रुपये से लेकर 93,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,18,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,01,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि

22 कैरेट सोने की कीमत 93,010 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,01,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,01,350 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 92,910 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,01,300 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 92,860 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,01,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,01,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 93,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 92,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,01,450 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 93,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोना महंगा हुआ है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 1,01,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 92,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जून में आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर सुस्त पड़कर 1.7 फीसदी पर

एजेंसी

नई दिल्ली। समावेशी आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ कदम के रूप में केंद्र सरकार की स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत अप्रैल 2022 से मार्च 2025 के बीच अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला उद्यमियों को करीब 29,000 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी गई। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कहा कि इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करके हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आत्मविश्वास से भरे नौकरी सृजक में बदलना है। सीतारमण ने कहा कि वित्तीय मदद के अतिरिक्त यह योजना हाशिए पर खड़े वर्ग को परामर्श, ट्रेनिंग और कौशल केंद्र, मेंटरशिप सहयोग, उद्यम विकास कार्यक्रम केंद्र, जिला उद्योग केंद्र जैसा विशेष प्रशिक्षण प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच के मूल्य के ऋण उस श्रेणी (रेटिंग) के लिए बैंक की न्यूनतम लागू दर पर उपलब्ध कराए गए हैं, जो आधार दर एमसीएलआर+3 फीसदी + अवधि प्रीमियम से अधिक नहीं थी, तथा पुनर्भुतान अवधि 7 वर्ष थी, तथा अधिकतम 18 महीने

STAND UP India
Endeavour and Prosper

तक की ऋण स्थगन अवधि थी। उल्लेखनीय है कि स्टैंड-अप इंडिया योजना 05 अप्रैल, 2016 को लॉन्च की गई थी। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण, सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 01 करोड़ रुपये के बीच मूल्य के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से ऋण उपलब्ध कराना था।

कमर्शियल कॉल के लिए चरणबद्ध तरीके से अपनायी जायेगी 1600 नंबर सीरीज

एजेंसी

नई दिल्ली । भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की एक बैठक में कमर्शियल कॉलों के लिए 1600 नंबर सीरीज को चरणबद्ध तरीके से अपनाने पर सहमति बनी है।ट्राई की संयुक्त नियामक समिति की हुयी बैठक में इस बात पर सहमति बनी। वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए लंबे समय से वाणिज्यिक कॉलों के लिए अलग नंबर सीरीज की मांग की जा रही थी। प्राधिकरण ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए समयसीमा पर फैसला नहीं हो सका था। समिति की मंगलवार को हुयी बैठक में सभी पक्ष इस बात सहमत हुये कि अलग-अलग सेक्टरों के नियामकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर चरणबद्ध तरीके से इसे अपनाया जायेगा। ट्राई के मुख्यालय में यहां आयोजित इस बैठक में रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भविष्य निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए डिजिटल सहमति पर शुरू किये गये पायलट पर भी चर्चा की गयी। इस पायलट में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अलावा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। सभी पक्षों ने मिलकर इसे आगे ले जाने पर सहमति जतायी है।

डॉलर के मुकाबले 5 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुआ रुपया, अन्य मुद्राओं की तुलना में भी आई गिरावट

एजेंसी

नई दिल्ली। स्टॉक मार्केट में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जमकर की गई बिकवाली के कारण आज रुपया डॉलर की तुलना में गिरावट के साथ बंद हुआ। मुद्रा बाजार में भारतीय मुद्रा आज डॉलर की तुलना में 5 पैसे फिसल कर 86.36 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुई। इसके पहले पिछले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय मुद्रा 86.31 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की मजबूती के साथ 86.25 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। दिन के कारोबार के दौरान कुछ समय के लिए डॉलर की आवक बढ़ने पर रुपया और 3 पैसे उछल कर 86.22 के स्तर तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों ने बिकवाली शुरू करके डॉलर की निकासी शुरू कर दी। ऐसा होने पर मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग बढ़

गई, जिससे रुपये पर भी दबाव बढ़ गया। डॉलर की मांग तेज होने पर रुपया ऊपरी स्तर से 20 पैसे फिसल कर 11 पैसे की कमजोरी के साथ 86.42 के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि बाद में मुद्रा बाजार में डॉलर की आवक बढ़ने पर रुपये की स्थिति में मामूली सुधार हुआ और भारतीय मुद्रा ने निचले स्तर से 6 पैसे की रिकवरी करके 86.36 के स्तर पर आज के कारोबार का अंत किया। कैपेक्स गोल्ड एंड इंवेस्टमेंट्स के सीईओ राजीव दत्ता का मानना है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार से अपने पैसे की निकासी के साथ वैश्विक बाजार में जारी उथल-पुथल ने आज भारतीय मुद्रा को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई।

उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत आज मामूली गिरावट आई है, इसके बावजूद मार्केट एक्सपर्ट्स के बीच इसकी कीमत में जल्दी ही तेजी आने की आशंका बनी हुई है। कीमत में तेजी आने की इस आशंका का असर आज मुद्रा बाजार में डॉलर की कीमत में तेजी के रूप में भी नजर आ रहा है।भारतीय मुद्रा रुपये ने डॉलर के साथ ज्यादातर दूसरी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले भी आज कमजोर प्रदर्शन किया। आज के कारोबार के बाद ब्रिटिश पौंड (जीबीपी) की तुलना में रुपया 42 पैसे की कमजोरी के साथ 116.56 के स्तर पर लुढ़क गया। इसी तरह यूरो की तुलना में रुपया आज 61 पैसे की गिरावट के साथ 101.10 के स्तर तक पहुंच गया।

दिव्यांका त्रिपाठी

ने एल्विश यादव को पहचाने में की गलती, फिर ट्रोल होने पर दिया करारा जवाब

टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों फिर एक बार सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं. दरअसल, 'लाफ्टर शेफ्स 2' शो के लेटेस्ट एपिसोड में दिव्यांका ने एल्विश यादव को पहचानने में एक छोटी सी गलती कर दी थी और इस गलती की वजह से यूट्यूबर एल्विश यादव के फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे थे. लेकिन अब दिव्यांका ने चुप रहने की बजाय, ट्रोलर्स को ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरे मामले का रुख ही बदल गया.'लाफ्टर शेफ्स' के सेट पर हुए सेमीफाइनल राउंड में दिव्यांका ने एल्विश यादव से हाथ मिलाते हुए गलती से 'हाय समर्थ' कहा था. उन्होंने गलती से एल्विश को समर्थ जुरेल समझ लिया था. दिव्यांका की इस गलती पर खुद एल्विश-समर्थ के साथ सेट पर मौजूद अली गोनी और कृष्णा अभिषेक जैसे स्टार्स भी हंस पड़े थे. लेकिन सोशल मीडिया पर एल्विश के फैंस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने दिव्यांका के अकाउंट पर निगेटिव कमेंट्स की भरमार कर दी.

दिव्यांका ने दिया करारा जवाब

आमतौर पर विवादों से दूर रहने वाली 'ये है मोहब्बतें' फेम दिव्यांका ने इस मुद्दे पर एल्विश फैंस को करारा जवाब दिया. उन्होंने सोमवार (21 जुलाई) को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, मैं एल्विश के सच्चे फैंस को धन्यवाद देना चाहती हूं, जो अच्छे थे. सच्चे फैंस अपने आइडल के सम्मान का ध्यान रखते हैं. साथ ही उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल करने वालों को फटकार लगाते हुए कहा, मेरी अंदर की आत्मा आपकी गंदी भाषा को आप और आपके परिवार की तरफ अपने आप लौटा देती है. कर्मा!

मानसिक शांति पर पड़ रहा है असर

दिव्यांका ने बताया कि उन्हें पहले ही अंदेशा था कि ये गलती ट्रोलिंग को बुलावा दे सकती है, इसलिए उन्होंने शो मेकर्स से उस पल को एडिट करने का अनुरोध भी किया था. लेकिन मेकर्स ने वो पार्ट ऐसे ही ऑन एयर कर दिया और इस वजह से दिव्यांका फैंस के निशाने पर आ गईं. एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे लगातार विवादों से उनकी मानसिक शांति पर असर पड़ रहा है. एल्विश यादव भी इस मामले में दिव्यांका की तरह ही सोचते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में ऑनलाइन ट्रोलिंग से तंग आकर कहा था, कभी-कभी मैं सोचता हूं, 'क्या इतना मशहूर होना अब गुनाह हो गया है? क्या मैंने कुछ गलत किया है?

बच्ची है यार करने दो...अमिताभ बच्चन के सामने बेटी पर भड़के थे शाहरुख खान, सुहाना की इस जिद ने दिलाया था गुस्सा

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन जल्द ही अपने क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के अगले सीजन के साथ छोटे पर्दे पर लौटने वाले हैं. अब तक इसके 16 सीजन आ चुके हैं और अब 17वां सीजन आ रहा है. इससे पहले हम आपको केबीसी के उस एपिसोड के बारे में बता रहे हैं, जब बिग बी के शो पर शाहरुख खान की बेटी और एक्ट्रेस सुहाना खान पहुंची थीं. तब बिग बी ने सुहाना को उनके बचन का एक मजेदार किस्सा सुनाया था.

अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान दोनों ही बॉलीवुड के बड़े दिग्गज हैं और दोनों के बीच मजबूत और खास बॉन्डिंग है. केबीसी में बिग बी ने वो किस्सा सुनाया था जब एक बार वो शाहरुख खान से किसी काम के सिलसिले में मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे. तब शाहरुख से बेटी सुहाना ने एक जिद की थी. जिस पर शाहरुख गुस्सा हो गए थे और उन्होंने सुहाना को जोर से डांट दिया था.

जब शाहरुख के घर पहुंचे थे अमिताभ

शाहरुख खान कई बार बिग बी के क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में शिरकत कर चुके हैं. वहीं सुहाना खान भी एक बार अमिताभ बच्चन के शो में पहुंची थीं. तब सुहाना को बिग बी ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा था, जब हम एक दिन आपके घर शाहरुख से मिलने के लिए, एक हमारी मीटिंग के लिए आए तब आपके घर पर नया-नया स्विमिंग पूल बना था. हम और शाहरुख वहीं स्विमिंग पूल के पास खड़े थे.

सुहाना को शाहरुख ने लगाई जोरदार डांट

अमिताभ बच्चन ने आगे कहा था, आप आईं और आपने कहा था मुझे स्विमिंग करना है. तो शाहरुख ने कहा नहीं, आप स्विमिंग नहीं करेंगी. मैंने कहा बच्ची है यार करने दो. तो शाहरुख ने कहा नहीं, नहीं. आप वापस जाओ. मुझे लगता है कि आपके पिता ज्यादा स्ट्रिक्ट थे. वो किस्सा मुझे अभी तक याद है. इस पर सुहाना ने कहा था, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे पहली बार नो कहा होगा. इस पर बिग बी ने कहा था, बहुत जोर से डांटा भी था आपको. दो तीन बार आपने कहा था मुझे स्विमिंग करना है, लेकिन शाहरुख ने कहा, नहीं.

'ये गंदी औरत है!' 'क्योंकि...' कि एक्ट्रेस को देखकर औरत ने कही ऐसी बात, आज भी दुखता है दिल

90's के सबसे चर्चित टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' जल्द ही वापसी करने जा रहा है. इस शो के सेकेंड सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शो की सबसे खास बात ये है कि शो के सेकेंड सीजन में पुरानी स्टारकास्ट वापसी कर रही है. शो के पुराने एक्टर्स के आने के सीरियल को लेकर हाइप भी अच्छी खासी है. सोशल मीडिया पर स्मृति इरानी और अमर उपाध्याय यानी तुलसी और मिहीर की जोड़ी को वापस से छोटे पर्दे पर देखने के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं. स्मृति और अमर के अलावा एकता कपूर के शो के पहले सीजन में एक्ट्रेस जया भट्टाचार्या ने भी अहम रोल अदा किया था. उन्होंने शो में पायल का किरदार निभाया था.

हाल में एक इंटरव्यू के दौरान, जया ने एक चौकाने वाली घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि एक बार स्मृति के साथ जब वो कहीं बाहर थीं, तो उनके साथ एक डराने वाला वाक्या हुआ, जिसे वो कभी दिमाग से निकाल नहीं पाएंगीं.

जया ने निभाया था पायल का किरदार

सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में क्योंकिञ एक्ट्रेस ने बताया कि एक बार उन्हें एक खतरनाक फैन मिल गया था. शो में जया ने पायल का किरदार निभाया था, जो एक निगेटिव किरदार था, ऐसे में जया को लोगों की काफी नफरत का भी सामना करना पड़ा था. जया ने बताया कि उन दिनों स्मृति प्रेग्नेंट थीं, और सात बजे की शिफ्ट थी. तो ब्रेक में दोनों पास में लोखंडवाला के एक कैफे में कुछ खाने के लिए चले गए. एक्ट्रेस ने बताया कि स्मृति और वो काफी अच्छी दोस्त हैं और ऐसे में वो स्मृति का हाथ पकड़कर चल रहीं थीं. इसी बीच वहां एक बूढ़ी महिला आई और जया का हाथ स्मृति से छुड़ाने लगी.

पहले कैमियो रोल कर रहीं थीं जया

जया ने आगे कहा कि उस औरत ने जबरदस्ती हाथ छुड़वाया और स्मृति से जया के लिए कहा कि ये गंदी औरत है, इसके आस-पास मत रहना. बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा. जया ने कहा कि उनको अपने किरदार के लिए काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा था. जया ने ये भी बताया कि उनका रोल पहले केवल कैमियो था, लेकिन बाद में इसे एक्सटेंड कर दिया गया. ये शो 29 जुलाई 2025 से स्टार प्लस पर आने वाला है.

चाचा ऋषि कपूर की इस फिल्म में काम करना चाहती थीं

करिश्मा

दादा की वजह से अधूरा रह गया सपना

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार के साथ काम किया है. 90 के दशक की सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से एक रहीं करिश्मा बड़े पर्दे पर अपने चाचा और दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर की एक फिल्म में भी नजर आना चाहती थीं. हालांकि एक्ट्रेस का ये ख्वाब अधूरा रह गया और इसके पीछे की वजह उनके दादा राज कपूर हैं.करिश्मा कपूर ने अपने करियर में खूब शोहरत हासिल की और बुलंदियों को छुआ. महज 17 साल की उम्र में लीड एक्ट्रेस बनने वाली करिश्मा को गजब की लोकप्रियता हासिल हुई थी, लेकिन उन्हें इस चीज का मलाल रह गया कि वो ऋषि कपूर की एक फिल्म में काम नहीं कर पाईं. करिश्मा ऋषि की हिट फिल्म 'हिना' में काम करना चाहती थीं.

'हिना' में काम करना चाहती थीं करिश्मा

करिश्मा ने बॉलीवुड में डेब्यू साल 1991 की फिल्म 'प्रेम कैदी' से किया था. लेकिन, वो इसके ठीक एक हफ्ते बाद रिलीज हुई फिल्म 'हिना' (1991) से बॉलीवुड में कदम रखना चाहती थीं. इसमें अहम रोल ऋषि कपूर ने निभाया था. बताया जाता है कि जब फिल्म को लेकर चर्चा चल रही थी जब करिश्मा ने इसमें काम करने की इच्छा जाहिर की थी.

राज कपूर की वजह से टूटा ख्वाब

राज कपूर ने जब इस फिल्म में ऋषि कपूर को कास्ट कर लिया तो करिश्मा का ख्वाब टूट सा गया. वहीं बाद में पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तियार की भी इसमें एंट्री हो गई. करिश्मा ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, मैं अपने पापा की फिल्म में काम करना चाहती थीं, लेकिन इसमें मेरे चाचा हीरो थे. अब तो भतीजी अपने चाचा के साथ हीरोइन का रोल नहीं कर सकती न. लेकिन, करिश्मा से उनके दादा राज साहब ने कहा था, लोलो बेबी मुझे पता है कि तुम एक्टर बनोगी, लेकिन मेरी सलाह है कि अगर एक्टर बनो तो बेहतर बनना, नहीं तो मत बनो.

जबरदस्त हिट हुई थी 'हिना'

हिना का डायरेक्शन पहले राज कपूर कर रहे थे, लेकिन उनके निधन के बाद इसकी बागडोर करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने संभाली थी. साढ़े तीन करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने 12 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.

दिव्य दिल्ली देवभूमि (हिमाचल)

दिल्ली, शुक्रवार
25.07.2025

infodivyadelhi@gmail.com

सेवा ही संकल्प: रजाना गांव के धर्म सिंह चौहान बन रहे निस्वार्थ सेवा की मिसाल

दिव्य दिल्ली : विजय आजाद (सिरमौर)

हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के उपमंडल संगड़ाह की ग्राम पंचायत रजाना से एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व सामने आया है – धर्म सिंह चौहान, जो वर्षों से झाड़-फूंक और पारंपरिक जड़ी-बूटियों के माध्यम से निःशुल्क उपचार कर रहे हैं। धर्म सिंह चौहान का यह सेवा कार्य न तो प्रचार के लिए है और न ही किसी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से। वे बचपन से ही जनसेवा

में लगे हुए हैं और अब तक हजारों लोगों को विभिन्न बीमारियों में राहत प्रदान कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन्होंने यह सेवा कार्य ईश्वर की प्रेरणा और जनकल्याण की भावना से प्रारंभ किया और जब तक शरीर साथ देगा, सेवा करते रहेंगे। मैंने यह कार्य किसी स्वार्थ के लिए नहीं शुरू किया। यह मेरे जीवन का संकल्प है। जब तक सांसें चलेंगी, लोगों की सेवा करता रहूंगा। – धर्म सिंह चौहान पत्रकार से बातचीत में दूर-दराज के क्षेत्रों से लोग पहुंचते हैं, जिनमें अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग होते हैं। निशुल्क भाव से सेवा करते हैं।

केवल श्रद्धा, अनुभव और आस्था के बल पर यह सेवा निरंतर जारी है।

चौधरी संदीप पंत को ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का कार्य प्रमुख नियुक्त किया

दिव्य दिल्ली : राजेश कतनौरिया (भरमाड़)

चौधरी फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष रोबिन कौंडल ने संगठनात्मक विस्तार और सामाजिक सेवा के दायरे को और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चौधरी संदीप पंत को ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का कार्य प्रमुख नियुक्त किया है। यह जानकारी आज भरमाड़ क्षेत्र में चौधरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रोबिन कौडल ने प्रेस वार्ता में बताया कि उनकी नियुक्ति से क्षेत्र में संगठन की गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। चौधरी संदीप पंत लंबे समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और अपनी बिरादरी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं।

न्यूज फ्लैश

केलांग में तहसीलदार का पद एक सप्ताह से खाली, जनसेवाएं ठप, जनता परेशान

दिव्य दिल्ली : रंजीत लाहौली (केलांग)

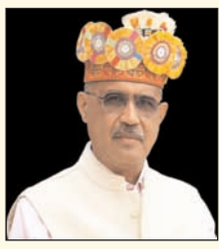

ज़िला मुख्यालय केलांग में तहसीलदार का पद बीते एक सप्ताह से खाली पड़ा है, जिससे राजस्व से जुड़े तमाम कार्य प्रभावित हो गए हैं। एसटी, एससी, बोनाफाइड, चरित्र प्रमाण पत्र से लेकर भूमि से संबंधित कार्यों की फाइलें लंबित पड़ी हैं। साथ ही होम स्टे पंजीकरण की प्रक्रिया भी पूरी तरह से रुक गई है। बैंकों से ऋण लेने के कामकाज भी ठप्प पड़ गए हैं। केलांग में तैनात तहसीलदार का एक सप्ताह पहले मंडी स्थानांतरण हो गया था। सरकार ने केलांग के लिए नए तहसीलदार की तैनाती के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन संबंधित अधिकारी ने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, जो रोजाना जरूरी प्रमाण पत्रों और जमीन से जुड़े कार्यों के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर काट रही है।पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता रवि ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लाहुल-स्पीति में विकास कार्य ठप्प हैं। तहसीलदार जैसे अहम पद को खाली छोड़ देना सरकार की लापरवाही को दशार्ता है। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्रों के अभाव में विद्यार्थी, परीक्षार्थी और सामान्य नागरिक सभी परेशान हैं। सरकार की नई नीति के अंतर्गत स्थानीय लोगों ने होम स्टे पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन एफिडेविट व भूमि दस्तावेज तैयार न होने से प्रक्रिया अधर में लटक गई है। इससे पर्यटन सीजन में स्थानीय लोगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। सरकार को तत्काल केलांग में तहसीलदार की नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नए तहसीलदार को कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि जनहित के कार्य सामान्य रूप से शुरू हो सकें।

कोटला नगर पंचायत की सीमा के समीप प्रस्तावित तारकोल प्लांट को निरस्त करने हेतु ज्ञापन

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के कोटला नगर पंचायत के नागरिक, आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के विषय में अपनी आपत्ति एवं चिंता प्रकट करते हुए आज सरकार के नाम पर नायब तहसीलदार प्रशासन को एक ज्ञापन सोपा ' इस अवसर पर मौजूद लोगों ने बताया कि बी सी आई पी एल कंपनी द्वारा देहर खड़ के समीप एक तारकोल प्लांट स्थापित करने की योजना काफी समय से बनाई जा रही है, जो कि कोटला नगर पंचायत की सीमा से अत्यंत निकट है। मौजूद लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र अब नगर पंचायत (कस्बा श्रेणी) में आता है ' यहाँ प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना न केवल असंगत है बल्कि कानूनी और पर्यावरणीय मानकों का भी उल्लंघन है। क्षेत्र वासियों ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, किसी भी प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाई की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर नगरीय क्षेत्र की सीमा से होनी चाहिए जबकि प्रस्तावित तारकोल प्लांट वास्तविकता में कोटला नगर पंचायत से 1 किमी से भी कम दूरी पर स्थित है। इस मामले में सरकार से मौजूद लोगों ने आग्रह किया कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए' जिससे किसी के स्वास्थ्य को नुकसान होता हो' प्लांट से निकलने वाली गैसें जनस्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालेंगी' जिसका असर विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों यह क्षेत्र पहले ही प्राकृतिक आपदाओं और भूस्खलन की चपेट में आ चुका है ' कोटला अब एक शहरीकृत क्षेत्र है, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े बुनियादी ढाँचे हैं वहाँ ऐसे प्रदूषणकारी प्लांट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर में मनाया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर ने वन विभाग के साथ मिलकर "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अंतर्गत गांव गहीं लगोड़ पंचायत में (थेरु वाली माता मंदिर, महाविद्यालय के नव- निमार्णाधीन भवन) के पास वन भूमि में पौधारोपण किया गया क इस अभियान में महाविद्यालय के इको क्लब, राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर एवं रेंजर क्लब के लगभग 55 वॉलिंटियर्स ने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ठाकुर, क्लब प्रभारी एवं शिक्षक गण, प्रभागीय वन अधिकारी श्री अमित शर्मा, सहायक वन संरक्षक श्री निशांत पराशर एवं वन मंडल कर्मचारी गण के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के लगभग 150 जंगली एवं औषधीय पौधे लगाए क पौधरोपण के लिए पौधे वन विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाए गए। वॉलिंटियर्स को इन पौधों की महत्ता एवं संरक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

ग्राम पंचायत भरमाड़ में मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना के तहत पशु डिस्पेंसरी खोली थी

विभाग के कर्मचारियों के लिए बैठने के लिए भी जगह कम है एक कमरे में ही बैठकर सारा काम करना पड़ता है

दिव्य दिल्ली : राजेश कतनौरिया (भरमाड़)

जवाली विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत भरमाड़ में पशुपालकों की मांग को मध्यनजर रखते हुए वर्ष 2010 में मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना के तहत पशु डिस्पेंसरी खोली थी जो आज भी लगभग 15 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी सामुदायिक भवन में चल रही है जो कि विभाग के कर्मचारियों के लिए बैठने के लिए भी जगह कम है एक कमरे में ही बैठकर सारा काम करना पड़ता है लोगों पवन कुमार, रमन कुमार , अशोक कुमार , जोगिन्दर सिंह , सतपाल सिंह, महिनदर सिंह, मुकेश कुमार, अमरनाथ ठाकुर ,गगन सिंह , व रवि कुमार ने बताया कि अगस्त 2017 में पूर्व सी पी एस नीरज भारती ने अपने कार्यकाल के दौरान पशु डिस्पेंसरी

को अपग्रेड करके इस पशु चकितसालय का दर्जा दिया था जो कि भरमाड़ वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात थी लेकिन भाजपा के पांच साल के कार्यकाल में इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया जो कि भवन बनवाने में भी नाकाम रही अपग्रेड होने से पहले लोगों को बरोह अस्पताल या रैहन असपताल मै पांच किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ता था पशु चिकित्सालय भरमाड़ आज लगभग 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी सामुदायिक भवन के एक कमरे में चल रहा है इस पशु चिकित्सालय के तहत सात डिस्पेंसरियां आती है सिद्धपुर-घाड़, नियाल -कनयाट, नियाल - दो, मैरा, पटाजाटियां भुगतियाल व कंदोर इन डिस्पेंसरियां के तहत लगभग 12 हजार पशु पालक आती है हालांकि पशु चिकित्सालय में कर्मचारियों के लिए शौचालय की भी सुविधा भी अभी तक नहीं है वो भी खुले में शौच करने को मजबूर है जनवरी 2021 में पंचायत द्वारा ई टायलेट के लिए पशु चकितसालय के प्रांगण मे खडडा खोदा था लेकिन आज दिन तक कैविन नहीं बना! भरमाड़ पशु चिकित्सालय मैं परमानेंट डॉक्टर की नियुक्ति तो कर दी है लेकिन एक ही कमरे में बैठकर काम करने मुश्किल पैदा हो रही है हैरानी की बात तो यह कि बेशक स्वच्छ भारत का स्वच्छ अभियान चला हुआ है लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों को शौचालय की सुविधा भी नहीं है वो भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं स्थानीय लोगों ने कृषि मंत्री चन्द्र कुमार चौधरी से मांग की है कि पशु चिकित्सालय के लिए भवन बनवाया जाये

कलर येलो और भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड की साझेदारी की धमाकेदार शुरूआत - एक थ्रिलिंग जॉनर-ब्लेंडर 'तू या मैं' के साथ

दिव्य दिल्ली : भारतीय सिनेमा में एक नए और साहसी अध्याय की शुरूआत करते हुए, निर्देशक आनंद एल राय की प्रोडक्शन कंपनी कलर येलो ने विनोद भानुशाली की भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। यह साझेदारी उन कहानियों को बढ़ावा देगी जो नई आवाजें, जॉनर की सीमाओं को तोड़ती सोच, और बड़े पर्दे के अनुभव के लायक सिनेमाई कहानियों को सामने लाएगी।इस सहयोग की पहली पेशकश है तू या मैं ।इक एक हाई-कॉन्सेप्ट, हाई-इमोशन डेट-फ्राइट फिल्म जो किसी एक श्रेणी में नहीं बंधती। शनाया कपूर और आदर्श गौरव की नई और रोमांचक जोड़ी के साथ यह फिल्म बिजॉय नांबियार के निर्देशन में बनी है, और यह एक ऐसे जॉनर-ट्विस्ट का वादा करती है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। एक मीट-क्यूट से शुरू होकर कहानी एक सर्वाइवल थ्रिलर में बदल जाती है। पृष्ठभूमि में संगीत, पागलपन और प्रकृति की अनिश्चितता का तूफान। भावनाओं से भरी और धारदार तू या मैं रोमांस और सर्वाइवल को एक ऐसे नैरेटिव में मिलाती है जो जॉनर की सीमाओं को तोड़ता है। फिल्म में अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट्स, दमदार म्यूजिक स्कोर, रैपर्स, बीट ड्रॉप्स और वाइब्रेंट साउंड डिजाइन है झ जो थियेटर में देखने का एक नया, बोल्ड अनुभव लेकर आता है। युवा दर्शकों

के लिए यह एक फ्रेश और हाई-कॉन्सेप्ट सिनेमा का परफेक्ट पैकेज है।

प्रोड्यूसर्स आनंद एल राय, हिमांशु शर्मा, विनोद भानुशाली और कमलेश भानुशाली एक ऐसी कहानी को समर्थन दे रहे हैं जो जितनी इमोशनली लेयर्ड है, उतनी ही विजुअली मंत्रमुग्ध कर देने वाली। राय और शर्मा की इनसानी जड़ों से जुड़ी कहानी और नांबियार की स्टाइलिश गहराई झ दोनों का मेल इसमें देखने को मिलेगा। फिल्म वेलेंटाइन्स डे 2026 पर रिलीज के लिए तय की गई है और पहले से ही इसे अगले साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक माना जा रहा है।कलर येलो के आनंद एल राय ने कहा, हर फिल्म के साथ हम ये तलाशते हैं कि कहानियाँ कितनी नई और अलग तरह से महसूस करवाई जा सकती हैं। तू या मैं उसी दिशा में एक साहसी और चौंकाने वाला कदम है। भानुशाली स्टूडियोज के साथ इस साझेदारी की शुरूआत करके मुझे बेहद खुशी है क्योंकि वे भी अप्रत्याशित को खोजने में विश्वास रखते हैं। भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड के विनोद भानुशाली ने कहा, हम जो भी करते हैं, उसके केंद्र में सिर्फ एक ही भावना है - ऐसी कहानियाँ सुनाना जो लोगों के दिलों को छू जाएँ। कलर येलो के साथ यह साझेदारी हमारी इसी रचनात्मक सोच और रिस्क लेने के जज्बे पर बनी है। तू या मैं के साथ हम एक बेहद रोमांचक, भावनात्मक और साहसी जोन में कदम रख रहे हैं।कलर येलो और भानुशाली स्टूडियोज मिलकर ऐसी फिल्मों की एक श्रृंखला बना रहे हैं जो डायरेक्टोरियल वीजन, जॉनर फ्लिप्स और हर मोड़ पर चौंकाने वाली कहानी कहने की कला से भरपूर हैं।

महाजन महिला विंग नूरपुर की महिलाओं ने किया सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर शहर में महाजन महिला विंग की एक बैठक आर्य समाज मंदिर नूरपुर में संपन्न हुई ' बैठक में महिला विंग की पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रही ' और इस बैठक के दौरान आर्य समाज मंदिर में महिला बिंग द्वारा सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया ' और इसके उपरांत कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में विशेष मुद्दा शहर में बढ़ते आवारा गोवंश के लिए गौशाला का निर्माण कराया जाए ' गोवंश की सेवा और सड़क पर रह रहे गोवंश के गलों में रेडियम वाले पट्टे लगाये जायें जो अब नूरपुर महाजन महिला विंग द्वारा लगाए जाएँगे।

इस अवसर पर कुछ महिलाओं ने सुझाव दिया कि आर्य समाज में बच्चों की एक कक्षा जरूर लगनी चाहिए जिस से आज के बच्चों को वैदिक मंत्रों का पाठ पढ़ाया जाए ताकि आज की पीढ़ी को वैदिक मंत्रों का ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हो, हमारे ग्रंथों का पता चले,' मीटिंग के समापन के बाद महिलाओं ने एक आर्य समाज मंदिर मे गेम्स खेली। यह जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति में महाजन महिला बिंग की प्रधान सोनिया महाजन ने दी

राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने विभिन्न अधिकारियों के साथ की बैठक

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पठानकोट के सचिव एवं सीजीएम रूपिंदर सिंह ने न्यायालय परिसर, पठानकोट में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पठानकोट के सचिव रूपिंदर सिंह ने बताया कि 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और

लोग संबंधित न्यायालय या सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन देकर अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की जीत होगी और कोई भी पक्ष अपना मामला नहीं हारेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायाधीशों द्वारा दिए गए फैसले के बाद, इस फैसले के खिलाफ किसी भी न्यायालय में दोबारा अपील नहीं की जा सकेगी, यह फैसला अंतिम होगा। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत के मामले के फैसले के बाद, कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में घरेलू विवाद, छोटे आपराधिक मामले, चेक बाउंस मामले, दुर्घटना मुआवजा मामले आदि का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आपसी सहमति से मामलों का निपटारा कर सामुदायिक भावना को बढ़ाएँ। इस अवसर पर विनय मरवाहा एलडीएम, हरजोत सिंह वरिष्ठ प्रबंधक, अजय कुमार, सुरिंदर सिंह लेखा अधिकारी, धीरज डोगरा उप-मंडल अभियंता आदि उपस्थित थे।

महिंद्रा पिकअप जीप और बुलेट मोटरसाइकिल की टक्कर में दो घायल

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

पठानकोट डलहौजी चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 ए पर गांव बुंगल के स्टेट बैंक के सामने एक महिंद्रा पिकअप जीप और बुलेट मोटरसाइकिल की आमने सामने हुई टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार महिला और व्यक्ति के घायल हो जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक महिंद्रा

पिकअप जीप नंबर पीबी 32 एच 0808 जोकि धार से पठानकोट की ओर जा रही थी कि जैसे ही जीप बुंगल के स्टेट बैंक के सामने पहुंची तो उसके आगे एक स्प्लेंडर मोटर साइकल नंबर पीबी 35 ए डी 9631 जा रही थी जिस पर एक व्यक्ति और एक महिला सवार थे और वह चक्की की ओर जा रहे थे को बचाते बचाते चक्की से बधानी की ओर जा रहे एक अन्य बुलेट मोटरसाइकिल नंबर पीबी 35 ए एन 0450 जिस पर भी एक व्यक्ति और एक महिला सवार थे के साथ जा टकराई । इस हादसे में बुलेट मोटरसाइकिल सवार चालक और महिला को गंभीर चोटें आईं हैं जबकि दूसरे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चालक और महिला को मामूली चोटें आईं हैं। घायल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सवारों को मामून के एक निजी अस्पताल में जबकि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सवारों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बधानी में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है। घायलों के नाम पता नहीं चल सके घायल बुलेट सवार गांव मट्टी कोट जबकि घायल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सवार गांव सिंलबा के निवासी बताए जा रहे हैं

शिकायतों को हल्के में लिया तो खैर नहीं : जिलाधिकारी

बरेली। जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने वाले अफसर अब सतर्क हो जाएं, क्योंकि जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है– शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा।

बीपीएल चयन के मानदंडों को बदलने के लिए सरकार से ग्राम पंचायत दिम्मी लोगों ने किया आग्रह

दिव्य दिल्ली : समित कुमार (हमीरपुर)

ग्राम पंचायत दिम्मी के वार्ड नंबर 2 गांव झम्बर ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल बीपीएल सर्वे की नई गाइडलाइन के विरोध में उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात की और अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी।पंचायत के लोगों ने नई गाइडलाइन के कारण लगभग 60 जरूरतमंद परिवार सूची से बाहर हो गए हैं जिससे और कुल दो परिवारों को बीपीएल सूची में रखा गया है। और अब उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। वहीं प्रवीण कुमार ने कहा कि पहले विकलांग, विधवा, वृद्ध व असहाय लोग ही बीपीएल सूची में शामिल होते थे लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार यदि विकलांगता 50 फीसदी से कम है या कोई व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है तो उसे बीपीएल में नहीं माना जा रहा भले ही उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो। कुछ परिवारों के पास मात्र दो पक्के कमरे हैं जिन्हें उनके पूर्वजों द्वारा या सरकारी सहायता से बनाया गया था उन्हें अमीर मान लिया गया है। ऐसे परिवार आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं और बच्चों की पढ़ाई व बुजुर्गों की दवा तक मुश्किल से कर पा रहे हैं। वहीं स्थानीय महिला ने कहा कि मैं बीमार रहती हूं और मेरा छोटा बेटा 75% मन बुद्धि है। और इनकम का कोई भी सोर्स हमारे पास नहीं है और हम बड़े बेटे के साथ उसके घर में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी मकान नहीं है कल को अगर मेरी मौत हो जाती है तो मेरे छोटे बेटे का क्या होगा जो मन बुद्धि है। उन्होंने कहा कि हमें बीपीएल सूची में डाला जाए ताकि मैं और मेरा बेटा अपना अच्छा से पालन पोषण कर सके। और साथ ही हमें सरकारी योजनाएं की सुविधा भी प्राप्त हो। वहीं स्थानीय ने कहा कि महिला ने कहा कि मेरे पति बीमार रहते हैं और मेरे घर में कमाने वाले मेरे पति थे और वह भी अब गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि हमें बीपीएल में डाला जाए ताकि हमें विभिन्न विभिन्न सरकारी सुविधा प्राप्त हो सके। पहले हम बीपीएल में थे जिससे हमें हर प्रकार की सुविधा प्राप्त होती थी। लेकिन अब सुविधा हमें नहीं मिल रही है हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें बीपीएल सूची में डाला जाए ताकि हम अपने परिवार पालन पोषण अच्छी तरह कर सके।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397